सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 73, नई दिल्ली । शनिवार, 25 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है।

03 वोटिंग से पहले मतदाताओं से चुनाव आयोग ने की ये खास अपील
06 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राजनीति
08 शाहपुरा जिले के राजकीय छात्रावात्सो में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा बिना पब्लिक नोटिस जारी किए वाहनों की फिटनेस बुराड़ी शाखा से प्राइवेट कम्पनी को फायदा पहुंचवाने के उद्देश्य से झुलझुली शाखा में आचार संहिता लागू होने पर भी भेजने के लिए इलेक्शन कमिशन को दी गई शिकायत

संजय बाटला

नई दिल्ली । परिवहन विभाग द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली के कम से कम 1.50 लाख वाहन मालिकों को इलेक्शन के इस दौर में अपने, अपने पारिवारिक सदस्यों और जानकार लोगो द्वारा मत का प्रयोग किसी विशेष पार्टी को कराने की सोच और प्राइवेट कम्पनी को फायदा पहुंचाने के प्रति कई आदेश किए और करने का प्रयास किया। इसी प्रकार के किए गए कार्य में है **बिना पब्लिक नोटिस जारी किए, बिना किसी पूर्व सूचना प्रदान किए और बिना किसी लिखित आदेश को जारी किए बुराड़ी फिटनेस शाखा से पिछले कई सालों से फिटनेस होने वाले वाहनों को अंदर ही अंदर झुलझुली फिटनेस शाखा में परिवर्तित कर देना और वह सब भी नियम और कानून को ताक पर रखकर ।** एक तरफ परिवहन विभाग के आला अधिकारी बैठक में यह कहते हैं कि आचार संहिता लागू है इसलिए अभी किसी भी कार्य पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा चाहे वह कार्य आचार संहिता से प्रभावित होने वाले भी नहीं हो और लागू हो सकतें हो और दूसरी तरफ इस तरह के आदेश, यह ऐसे आदेश है जो दिल्ली में लाखों वोटरों का मन किसी पार्टी को वोट देने से बदलने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते है। क्या सच में परिवहन विभाग के आला अधिकारी इसी लिए बिना पब्लिक नोटिस जारी किए ऐसे कार्य करवा रहे हैं, बड़ा सवाल ? यह भी देखना होगा की इलेक्शन कमिशन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई करता है या इसे कचरे में फैंक देता है, क्योंकि परिवहन विभाग दिल्ली के आला अधिकारियों के ऊपर आलाओ का हाथ जो है।

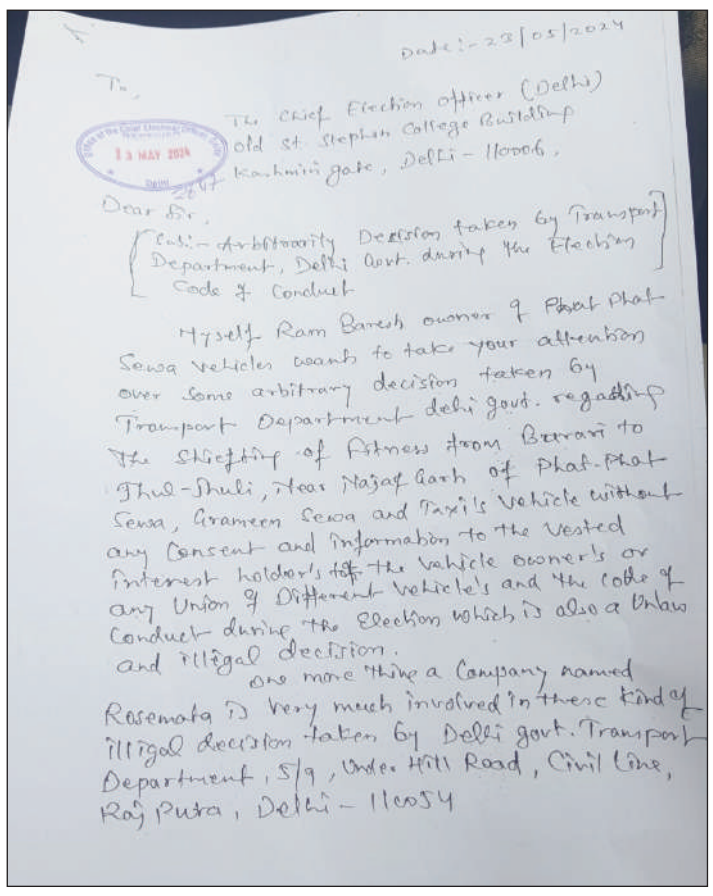

Date :- 23/05/2024

To,
The Chief Election officer (Delhi)
Old St. Stephen College Building
Kashmiri gate, Delhi - 110006.

13 MAY 2024

Dear Sir,
[Sub:- Arbitrarity Decision taken by Transport Department, Delhi Govt. during the Election Code of Conduct]

Myself Ram Baresh owner of Phat Phat Sewa vehicles want to take your attention over some arbitrary decision taken by Transport Department delhi govt. regarding the shifting of fitness from Burari to Jhul-Jhuli, Near Najaf Garh of Phat-Phat Sewa, Grameen Sewa and Taxi's vehicle without any consent and information to the vested interest holder's of the vehicle owner's or any Union of Different vehicle's and the code of conduct during the Election which is also a Unlaw and illegal decision.

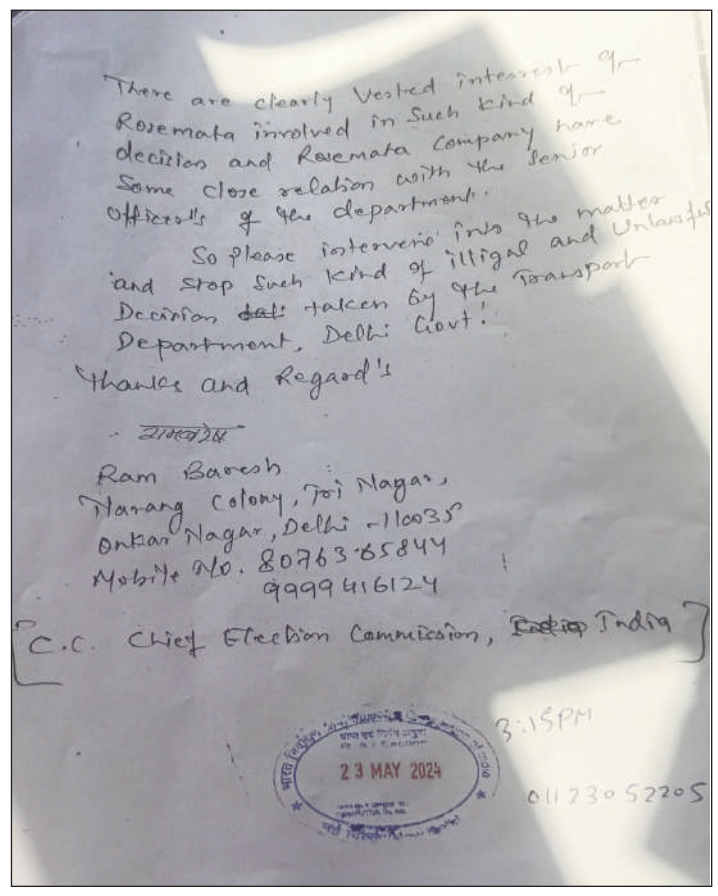

one more thing a Company named Rosemata is very much involved in these kind of illegal decision taken by Delhi govt. Transport Department, 5/9, Under Hill Road, Civil Line, Raj Pura, Delhi - 110054

There are clearly vested interest of Rosemata involved in such kind of decision and Rosemata company have some close relation with the senior officer's of the department.

So please intervene into the matter and stop such kind of illigal and Unlawful Decision taken by the Transport Department, Delhi Govt.

Thanks and Regard's

रामबरेश
Ram Baresh
Narang Colony, Tri Nagar,
Onkar Nagar, Delhi - 110035
Mobile No. 8076365844
9999416124

[C.C. Chief Election Commission, India]

3:15PM
23 MAY 2024
01123052205

शनिवार को सुबह 4 बजे से चलेंगी मेट्रो और डीटीसी की बसें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीटीसी और डीएमआरसी ने फैसला लिया है कि शनिवार को मेट्रो और डीटीसी की बसें सुबह 4 बजे से चलेंगी। 4 से 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल में मेट्रो चलेंगी। 6 बजे के बाद सामान्य मेट्रो ट्रेन सेवाएं पूरे दिन चलेंगी।

झज्जर/बहादुरगढ़ । देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। शनिवार को हरियाणा में मतदान होगा। मतदान में डीटीसी और दिल्ली मेट्रो ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम फैसले लिए हैं। इसमें डीटीसी और मेट्रो सेवाएं शनिवार को सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। यह हर 30 मिनट के अंतराल में चलेंगी। 6 बजे के बाद सामान्य मेट्रो ट्रेन सेवाएं दिन भर जारी रहेंगी। डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुज दयाल ने बताया कि 25 मई को दिल्ली-हरियाणा में लोकसभा चुनाव हैं। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों समेत मतदाताओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मेट्रो का परिचालक सुबह 4 बजे किया है।

उनके अनुसार सुबह 6 बजे के बाद से मेट्रो का परिचालक सामान्य दिनों की तरह किया जाएगा। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हर 30 मिनट में मेट्रो सेवाएं सभी स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीटीसी बस सेवा का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू होगा। बता दें कि बहादुरगढ़ से ज्यादा दिल्ली में डीटीसी का परिचालन होता है। हालांकि बहादुरगढ़ से चलने वाली बसें सुबह अपने समय से जल्दी चलेंगी। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली परिवहन निगम के प्रवक्ता के अनुसार शनिवार को सुबह 4 बजे से बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली शहर के 35 प्रमुख मार्गों पर सुबह चार बजे से बस सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।

वाहन परमिट में फर्जीवाड़ा, कोर्ट के आदेश की अनदेखी, आखिर की किसने और क्यों, जानें?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली । पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली परिवहन विभाग की तरह नई व्यवस्था के तहत प्रदेश भर के कई आरटीओ कार्यालयों में डिप्टी कलेक्टर स्तर के राजस्व से जुड़े अधिकारियों को जिला और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर बिठा दिया गया । परिवहन के नियमों से अनजान इन अधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय में काम कराने के लिए आने वाले नागरिकों से जमकर वसूली करी और **इसी का फायदा बाबुओं अधिकारियों ने भी उठाया और परमिट तथा अन्य दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर दिया ।** कोर्ट ने आरटीओ के राजधानी स्थित कार्यालय को लेकर गंभीर टिप्पणी की और आदेश भी जारी किये। इस आदेश से सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में बिगड़ी हुई व्यवस्था को कड़ाई से सुधारने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परमिट मामले में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर रायपुर आरटीओ को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जल्द से जल्द पूरा स्टाफ बदलने का आदेश भी दिया। इसके साथ ही रायपुर के खमतराई थाना प्रभारी को भी 10 बजे तक हाजिर न होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट रूम में ही रहने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में हो रही गड़बड़ी और परमिट को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है। **ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश के किसी आरटीओ कार्यालय में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर मामला कोर्ट में दायर किया गया हो और कोर्ट ने इस तरह की अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कार्यालय के पूरे स्टाफ को बदलने तक का आदेश दे दिया।**

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के बावजूद यात्रियों की संख्या में 30 प्रतिशत का इजाफा

कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि पिछले एक साल में मेट्रो रेल में सफर करने वाले लोगों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली । कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि पिछले एक साल में मेट्रो रेल में सफर करने वाले लोगों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भले ही 'शक्ति' गारंटी के तहत कर्नाटक की महिलाओं को राज्य भर में नॉन-लग्जरी सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए निःशुल्क सवारी की पेशकश की जाती है।

रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कथित बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा मेट्रो रेल राजस्व को प्रभावित करेगी।

रेड्डी के अनुसार, 11 जून, 2023 को राज्य में शक्ति गारंटी लागू की गई थी और तब से 20 मई तक शहर में महिलाओं द्वारा 67.34 करोड़ निःशुल्क यात्राएं दर्ज की गई हैं। मंत्री ने एक बयान में कहा, ₹पिछले एक साल में हमारी मेट्रो रेल राइडरशिप में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2023 में, मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या 1.65 करोड़ थी और राजस्व 39.15 करोड़ रुपये था। अप्रैल 2024 में, यात्रियों की संख्या बढ़कर दो करोड़ हो गई और राजस्व बढ़कर 51.71 करोड़ रुपये हो गया।₹

उनके अनुसार, 2024 में 2023 की तुलना में प्रति माह 35 लाख यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है। और राजस्व में प्रति माह 1.10 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

रेड्डी ने कहा, इन आंकड़ों से साफ है कि मेट्रो रेल शक्ति गारंटी से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। बल्कि, मेट्रो राइडरशिप और राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए "पूर्वाग्र से ग्रस्त होना" और योजना को दोष देना "उचित नहीं" है।

3500 करोड़ की लागत से बना है यह राष्ट्रीय राजमार्ग, डबल इंजन की रफ्तार से रिश्ते और हुए प्रगाढ़

परिवहन विशेष न्यूज

गुरु गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की नगरी का रिश्ता और प्रगाढ़ हुआ है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पर सवार होकर विकास ने फर्राटा भरा तो सीएम सिटी से पीएम सिटी बनारस 10 से घटकर चार घंटे के फासले पर आ गई। यह फोरलेन सामाजिक-आर्थिक बदलाव का सूत्रधार बनकर उभर रहा है। अरुण चन्द की रिपोर्ट...

सात साल पहले तक सोनभद्र से गिट्टी और मौरंग के ट्रक चलते थे। ये कभी जाम में फंस जाते तो कभी गड्ढों की वजह से खराब हो जाते थे। गोरखपुर आने में 18 से 20 घंटे लग जाते थे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गोरखपुर एवं आसपास के जिलों के लोग हों या फिर वाराणसी से गुरु गोरक्षनाथ, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर या फिर नेपाल आने को इच्छुक पर्यटक, सड़क मार्ग को अंतिम विकल्प के रूप में चुनते थे।

गोरखपुर से वाराणसी तक चौड़ी व गड्ढा मुक्त सड़क की जरूरत को हर सरकार मानती थी, लेकिन यह संभव तब हुआ जब केंद्र के बाद प्रदेश में भी 2017 में भाजपा की सरकार आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क को फोरलेन करने की मांग उठाई और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रख दी। 3500 करोड़ की लागत से छह साल में जब सड़क बनकर तैयार हुई तो आज विकास भी फर्राटा भरने लगा है।

10 घंटे की दूरी महज चार घंटे में पूरी हो जा रही है। सुबह घर से निकलकर रात तक वापस आने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता। गोरक्षनगरी व आसपास के जिलों के लोगों के लिए अब बाबा विश्वनाथ दूर नहीं हैं तो काशी के लोगों के लिए गुरु गोरक्षनाथ। बेलीपार के व्यापारी विजय मोदनवाल बताते हैं कि अब वाराणसी से आना-जाना आसान हो गया है।

225 किमी की दूरी तक सड़क किनारे के कई वीरान पड़े क्षेत्र गुलजार हो गए हैं, तमाम लोग आत्मनिर्भर बनने के साथ औरों को भी रोजगार देने की स्थिति में हैं। व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। कई शिक्षण संस्थान यहां खुले हैं। कई की नींव पड़ी है। हाईवे के दोनों किनारों पर कई होटल, ढाबे और बाजार विकसित हुए हैं।

भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर और कबीर स्थली मगहर। दुनिया का कोई भी हिस्सा अलग-अलग परंपराओं में सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है। इसके बावजूद यह क्षेत्र सात साल पहले तक पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा ही रहा, लेकिन गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन के निर्माण से अब तस्वीर बदल रही है।

गोरखपुर नए पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और इसमें काशी से गोरक्षनगरी को जोड़ने वाली फोरलेन सड़क का भी बड़ा योगदान है। कुशीनगर हो या नेपाल बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी से गोरखपुर होकर ही जाते हैं। पर्यटक बढ़े तो कभी गिनती के होटलों वाला गोरखपुर अब होटल हब के रूप में पहचान लेने लगा है।

सरयू नदी पर पुल का सपना हुआ साकार

बड़हलगंज के संजय श्रीवास्तव बताते हैं कि एक महीना पहले तक गोरखपुर से वाराणसी के बीच सिर्फ बड़हलगंज बाईपास पर सरयू नदी का पुल अधूरा रह जाने से सफर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब वह भी दूर हो गई।

एनएचएआइ प्रशासन ने 14 अप्रैल से पुल की एक लेन आवागमन के लिए खोल दिया। दूसरी लेन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एनएचएआइ के परियोजना प्रबंधक ललित पाल के मुताबिक, जल्द ही यह लेन भी बनकर तैयार हो जाएगी।

बढ़ा शहर का दायरा

फोरलेन बनने से कनेक्टिविटी सुधरी तो शहर की सीमा का भी विस्तार हुआ। 2020 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपना दायरा बढ़ाकर गोरखपुर-वाराणसी रोड पर पड़ने वाले महावीर छपरा तक कर लिया। यह विस्तार लगभग 15 किलोमीटर का रहा। अब इन क्षेत्रों में जीडीए की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

इसी क्षेत्र के ताल नदोर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है। इसी रोड पर वेटरनरी कालेज के लिए 100 एकड़ जमीन प्रशासन द्वारा दी जा चुकी है। इसकी आधारशिला भी रखी जा चुकी है। कुछ आवासीय योजनाएं भी यहां प्रगतिशील हैं। प्राइवेट कालोनाइजर्स ने भी यहां बड़ा निवेश किया है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

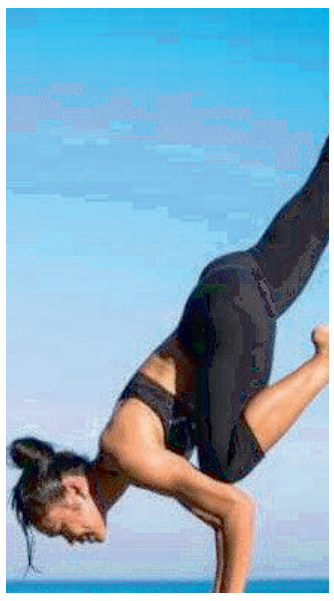

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें. अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें. इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं.

इ

स आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को

महिलाएं 'घर का काम' करना बंद कर दें तो क्या होगा?

अनंत प्रकाश

चीन की एक अदालत ने हाल ही में तलाक़ से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है. कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह पाँच साल तक चली शादी के दौरान पत्नी द्वारा किए गए घरेलू काम के बदले में उसे मुआवजा दे. इस मामले में महिला को 5.65 लाख रुपये दिए जाएंगे.

लेकिन इस फ़ैसले ने चीन समेत दुनिया भर में बड़ी बहस को जन्म दिया है. चीनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस मामले में लोगों की राय बंटी हुई है.

कुछ लोगों का मानना है कि महिला घर के काम के बदले में मुआवज़े के रूप में कुछ भी लेने की हक़दार नहीं हैं. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि जब महिला अपने करियर से जुड़े अवसरों को त्याग कर हर रोज़ घंटों घरेलू काम करती हैं तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए.

इससे पहले जनवरी महीने में भारत की सर्वोच्च अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि ₹घर का काम परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है.₹

और ये पहला मौका नहीं था अदालतों ने 'घर के काम' को आर्थिक गतिविधि के रूप में स्वीकृति दिलाने वाले फ़ैसले दिये हों. चीन से लेकर भारत और पश्चिमी दुनिया के देशों में अदालतें बार - बार महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम (अनपेड लेबर) को आर्थिक उत्पादन के रूप में स्थापित करने वाले फैसले देती रही हैं.

लेकिन इसके बावजूद 'घर के काम' को जीडीपी में योगदान के रूप में नहीं देखा जाता है. यही नहीं, समाज घर के काम को वह अहमियत नहीं देता है जितनी नौकरी या व्यवसाय में किए गए काम को देता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं 'घर के काम' छोड़कर नौकरी या व्यवसाय शुरू कर दें तो क्या होगा.

'घर के काम' के मायने क्या हैं?

दुनिया की अधिकांश महिलाएं इस सवाल से जूझती हैं कि समाज एक गृहिणी के रूप में उनके द्वारा किए गए 'घर के काम' को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता जो पुरुषों द्वारा किए गए काम को दिया जाता है.

जबकि एक गृहिणी के रूप में महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों के किए गए काम के घंटों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं.

सालों तक पत्रकारिता के साथ-साथ घरेलू काम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां उठाने वाली कृतिका खुद इस सवाल से जूझ रही हैं.

वे कहती हैं, ₹मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग घर के काम को अहमियत क्यों नहीं देते? ऐसे माना जाता है कि घर का काम मतलब कोई काम ही नहीं. जबकि घर के काम आसान नहीं होते. घर पर अगर किसी को तय समय पर दवा देनी है, तो वो काम करना है, खाना तय समय पर बनना है, तो बनना है. इसमें किसी तरह की राहत नहीं मिलती.

इन सबके बाद अगर किसी को शाम को भूख लग गई तो उसके लिए भी कुछ न कुछ बनाना होता है. सही कहूं तो घर के काम करने वाली महिला को 'अलादीन का चिराग़' समझा जाता है. मेरे पास इससे सटीक मेटाफ़र नहीं है. अगर कभी सहयोग की माँग की भी जाए तो कहा जाता है कि करती ही क्या हो... मम्मी भी करती थीं उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा.

महिला, अवैतनिक श्रम

आँकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत में घर के काम में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं.

ताजा टाइम यूज़ सर्वे के मुताबिक़, महिलाएं हर दिन घर के काम (अवैतनिक घरेलू कार्य) में 299 मिनट लगाती हैं. वहीं, भारतीय पुरुष दिन में सिर्फ 97 मिनट घर के काम में लगाते हैं.

यही नहीं, इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि महिलाएं घर के सदस्यों का ख़याल रखने में रोज़ 134 मिनट लगाती हैं. वहीं, पुरुष इस काम में सिर्फ 76 मिनट ख़र्च करते हैं.

आर्थिक मूल्य निकालना मुश्किल है?

ध्यान से देखें तो हर काम का कोई न कोई मूल्य होता है. तो ये कैसे संभव है कि महिलाओं द्वारा घर पर रहकर किए गए काम की कोई आर्थिक मूल्य न हो?

किसी भी काम का मूल्य निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस काम का ठीक-ठीक आकलन किया जाए. महिलाओं के किए गए अवैतनिक घरेलू श्रम यानी 'घर के काम' का मूल्य निकालने के लिए तीन फॉर्मूले उपलब्ध हैं -

अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड इनपुट/आउटपुट कॉस्ट मेथड

पहले फ़ॉर्मूले के मुताबिक़, अगर कोई महिला बाहर जाकर पचास हज़ार रुपये कमा सकती है और इसके बावजूद वह घर के काम करती है तो उसके काम की कीमत पचास हज़ार रुपये मानी जानी चाहिए.

वहीं, दूसरे फ़ॉर्मूले के मुताबिक़, एक महिला द्वारा किए गए 'घर के काम' का मूल्य उन सेवाओं के लिए किए किए जाने वाले खर्च के आधार पर तय होती है. सरल शब्दों में कहें तो अगर एक महिला की जगह घर पर कोई और काम करता है तो जो ख़र्च उसकी सेवाएं लेने के बदले में होगा, वही उस महिला के द्वारा किए गए काम का मूल्य होगा.

इसी तरह तीसरे फॉर्मूले में एक महिला द्वारा घर पर किए गए काम की मार्केट वेल्यू निकाली जाती है.

लेकिन इनमें से कोई भी फॉर्मूला भावनात्मक रूप से दी गई सेवाओं का सही मूल्य नहीं निकालता है.

अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान

अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम के एक अध्ययन के मुताबिक़, महिलाओं द्वारा किए गए 'घर के काम' का मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था का 3.1 फीसदी है.

साल 2019 में महिलाओं द्वारा किए गए 'घर के काम' की क़ामत दस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा थी. ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की पचास सबसे बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट, ऐप्पल और अमेज़न आदि की कुल आमदनी से भी ज़्यादा थी.

इसके बाद भी भारतीय अदालतों को बार-बार गृहणियों के काम को आर्थिक मायने देने के लिए फ़ैसले देने पड़ते हैं.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है, ₹एक गृहिणी की आमदनी को निर्धारित करने का मुद्दा काफ़ी अहम है. यह उन तमाम महिलाओं के काम को मान्यता देता है, जो चाहे विकल्प के रूप में या सामाजिक/सांस्कृतिक मानदंडों के परिणामस्वरूप इस गतिविधि में लगी हुई हैं.

यह बड़े पैमाने पर समाज को संकेत देता कि क़ानून और न्यायालय गृहणियों की मेहनत, सेवाओं और बलिदानों के मूल्य में विश्वास करता है.₹

यह इस विचार की स्वीकृति है कि ये गतिविधियां परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करती हैं और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं. इस तथ्य के बावजूद इन्हें पारंपरिक रूप से आर्थिक विश्लेषण से बाहर रखा गया है. यह बदलते दृष्टिकोण, मानसिकता और हमारे अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों का प्रतीक है. और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामाजिक समानता की संवैधानिक दृष्टि की ओर एक कदम है और सभी व्यक्तियों को जीवन की गरिमा सुनिश्चित करता है.₹

कामकाजी महिलाओं की बेटियों का करियर बेहतर?

महिलाएं जो काम करती हैं वो क्या है?

ध्यान से देखें तो गृहणी के रूप में काम के दौरान महिलाएं तीन वर्गों को अपनी सेवाएं देती हैं. पहला वर्ग वरिष्ठ नागरिक जो देश की आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे चुके होते हैं, दूसरा युवा वर्ग जो वर्तमान में जीडीपी में योगदान दे रहे हैं और तीसरा बच्चे जो आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे.

तकनीकी भाषा में इसे अब्सट्रेक्ट लेबर कहा जाता है. ये एक ऐसा श्रम है कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रम के पुनर्जीवन में सीधे-सीधे अपना योगदान देता है.

भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुशीला चानू अपने घर में चाय बनाते हुए

सरल शब्दों में कहें तो एक महिला अपने पति के कपड़े धोने, प्रेस करने से लेकर उसके खाने-पीने, शारीरिक एवं मानसिक सेहत आदि का ख़याल रखती है ताकि ऑफ़िस जाकर काम कर सके. वह बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो बाद में देश के मानव संसाधन का हिस्सा बन सकें. वह अपने माता-पिता और सास-ससुर की सेहत का ध्यान रखती हैं जो देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे चुके होते हैं.

अब अगर इस पूरे समीकरण में से गृहणी को निकाल दिया जाए तो सरकार को बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाल कल्याण सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के वृद्धाश्रम, केयर गिवर आदि पर बेतहाशा खर्च करना पड़ेगा.

क्या होगा अगर महिलाएं काम बंद कर दें?

फिलहाल, ये काम ग्रहणियां कर रही हैं जो मूलतः सरकार के हिस्से का काम है क्योंकि एक नागरिक की देखभाल की ज़िम्मेदारी राष्ट्र की होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं फ्री में सरकार के लिए काम करना बंद कर दें तो क्या होगा?

असंगठित क्षेत्र एवं श्रम से जुड़े विषयों पर अध्ययन कर चुकीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर अर्चना प्रसाद मानती हैं कि यदि महिलाएं घर के काम ही बंद कर दें तो ये सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा.

वे कहती हैं, महिलाएं ये अनपेड काम करना बंद कर दें तो पूरा तंत्र ही ठप हो जाएगा. क्योंकि महिला का अनपेड वर्क ही तो सिस्टम को सब्सिडाइज़ करता है. अगर घर के काम और केयर से जुड़े काम का ख़र्च सरकार या कंपनियों को वहन करना होगा तो श्रम की मूल्य काफ़ी बढ़ जाएगा.

क्योंकि महिलाएं श्रम शक्ति को पुनर्जीवित कर रही हैं. उसे संभाल रही हैं. इस तरह से हर आदमी के श्रम में महिला का अनपेड श्रम शामिल है. तकनीकी भाषा में हम इसे अब्सट्रेक्ट लेबर कहते हैं.

महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू काम को जीडीपी में योगदान के रूप में स्वीकार्यता दिलाने की पक्षधर अर्थशास्त्री, लेखिका और न्यूजीलैंड की राजनेता मर्लिन वैरिंग मानती हैं कि जीडीपी में महिला द्वारा गर्भधारण तक को एक उत्पादक गतिविधि नहीं माना जाता है जबकि वह भविष्य के मानव संसाधन को जन्म देती हैं.

अपने देश का उदाहरण देते हुए वे कहती हैं, ₹न्यूजीलैंड के नेशनल अकाउंट्स, जहां से जीडीपी के आँकड़े मिलते हैं, में गाय, बकरी, भेड़ और भैंस के दूध की कीमत है लेकिन माँ के दूध की कोई कीमत नहीं है जबकि वह दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है. ये बच्चे की सेहत और शिक्षा में सबसे अच्छा निवेश है लेकिन इसे गिना नहीं जाता है.₹

आर्थिक पहचान कैसे दी जाए?

अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर के काम को किस तरह आर्थिक पहचान दी जा सकती है.

अवैतनिक श्रम पर कई किताबें लिख चुकीं अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर इंदिरा हीरवे मानती हैं कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को एक उत्पादन की तरह देखा जाना चाहिए.

वे कहती हैं, ₹घर में महिलाएं जो खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाज़ार से सामान लाती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, घर में बीमार लोगों का ख़याल रखती हैं - वो सर्विस है यानी सीधे-सीधे उत्पादन से जुड़ा है. ये काम देश की आमदनी और देश को सेहतमंद रखने में उनका योगदान है.₹

अगर एक नर्स की सेवाएं ली जाएं तो उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है. लेकिन यही काम अगर एक गृहिणी करे तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है. ये ग़लत बात है. जबकि काम तो वही है. इसका कोई कारण ही नहीं है कि इन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाए. यही नहीं, वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं. सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तकल कोई भी महिलाओं के लिए इस अवैतनिक श्रम के बिना नहीं चल सकते.₹

इतिहास के पन्ने पलटें तो एक समय ऐसा आया है जब वो हुआ है जिसके संकेत प्रोफ़ेसर हीरवे ने दिए हैं.

साल 1975 में आइसलैंड की नब्बे फीसदी महिलाओं ने 24 अक्तूबर को एक दिन के लिए खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया. महिलाओं के इस ऐलान का असर ये हुआ कि पूरा देश एकाएक रुक गया. काम पर गए पुरुषों को तत्काल घर वापसी करनी पड़ी और बच्चों को रेस्त्रां लेकर भागना पड़ा और वे सभी काम रुक गए जो कि आमतौर पर पुरुष किया करते थे.

लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी महिलाएं इस तरह का अवैतनिक श्रम करना बंद कर दें तो वही होगा जो 1975 में हुआ था.

'ख़त्म हो जाएंगे परिवार'

प्रोफ़ेसर हीरवे मानती हैं कि अगर महिलाएं घर पर काम करना बंद कर दें तो परिवार नाम की संस्था ही ख़त्म हो जाएगी.

वे कहती हैं, ₹विकास के मायने ये होते हैं कि सभी लोग अपने मन का काम कर सकें. जो महिला डॉक्टर बनना चाहे वह डॉक्टर बन सके, जो महिला इंजीनियर बनना चाहे वह इंजीनियर बन सके.₹

₹लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं पर घर के काम थोप दिए हैं. इससे उनके पैरों में एक तरह की बेड़ियां पड़ गई हैं. उन पर ये दबाव है कि वे पहले घर के काम करें फिर कोई अन्य काम करें. अगर वे काम करना बंद कर दें तो सबसे पहले परिवार नामक संस्था ख़त्म हो जाएगी. यही नहीं, निजी क्षेत्र से लेकर सरकारी क्षेत्र आदि का काम ख़त्म हो जाएगा. आपको ये मानना होगा कि अवैतनिक श्रम के बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती.₹

इंदिरा नूई का उदाहरण देते हुए हीवरे कहती हैं कि औपचारिक व्यवसायिक तंत्र में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद घर संभालने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है. वे कहती हैं, ₹एक बार इंदिरा नूई ने बताया था कि तमाम सुख-सुविधाओं के बावजूद घर चलाने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है. उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था. कंपनी में एक बार उन्हें प्रमोशन मिला. वे घर पहुंचीं तो दरवाज़े पर उन्हें माँ मिली जिन्होंने कहा कि जाओ जाकर दूध ले आओ, तुम्हारे पति और बच्चों को सुबह दूध की ज़रूरत होगी. इंदिरा पहले दूध लेने गईं. तो मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी तो महिलाएं की ही होती है. ये बात कई महिला सीईओ ने भी कही है कि वे चाहे कितना तरक्की कर लें उन्हें इन कामों से छुटकारा नहीं मिल सकता है क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है.₹

इंदिरा हीरवे मानती हैं कि भारत को अपनी जीडीपी में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक श्रम को शामिल करना चाहिए. वे कहती हैं, ₹भारतीय मौद्रिक जीडीपी की दूसरे देशों से तुलना करना ग़लत है क्योंकि भारत में महिलाएं अवैतनिक श्रम करके राष्ट्रीय आय में जो योगदान दे रही हैं उसे जीडीपी में गिना ही नहीं जाता. जबकि विदेशों में यही काम फोस्टर केयर, ओल्ड एज होम, नर्स, नैनी आदि रूपों में राष्ट्रीय आय में शामिल होता है.₹

क्या है समाधान?

दुनिया भर में कई महिलाएं और पुरुष इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से लेकर समाज में पितृसत्ता का असर कम होना चाहिए.

जागो री मूवमेंट को चलाने वालीं कमला भसीन मानती हैं कि पहली लड़ाई तो यही है कि हम पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलें.

वे कहती हैं, ₹आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि पुरुषों को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वे अपनी बड़ी होती बेटी या बेटे के साथ जी भर के समय गुज़ार सकें. उन्हें पढ़ा लिखा सकें, उनके साथ खेल सकें.₹

पुरुष जो करते हैं वह जीविकोपार्जन का जुगाड़ है. ये जीवन नहीं है. आपकी पत्नी जो जी रही हैं, वह जीवन है. आप कुछ समय नौकरी न करें तो आपके बच्चों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आपकी पत्नी एक दिन काम न करें तो जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा हो जाता है.

सोचकर देखिए कि आज अगर महिलाएं कह दें कि या तो हमारे साथ सही से व्यवहार करें नहीं तो हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे. क्या होगा? होगा ये कि सेनाएं ठप हो जाएंगी. मानव संसाधन कहां से लाएंगे आप?

लेकिन सवाल उठता है कि कहीं घर के काम को आर्थिक गतिविधि का दर्जा दिलाने की लड़ाई बहुत लंबी तो नहीं है.

पेड़-पौधों पर शोध करने वालीं रुचिता दीक्षित मानती हैं कि जहां से ग़लती शुरू हुई है, सुधार भी वहीं से शुरू होगा.

वे कहती हैं, ₹मैं एक वैज्ञानिक हूं. लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मेरे सामने ये सवाल था कि अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार या नैनी के हवाले छोड़ दूं या नौकरी छोड़कर उसके पालन-पोषण में अपना योगदान दूं. मैंने दूसरा विकल्प चुना. लेकिन मैंने ये विकल्प चुनते हुए लोगों को ये अहसास कराया है कि ये कोई आसान काम नहीं है.₹

₹सुधार हम से ही होगा. मुझे लगता है कि हमें आने वाले कल में अपनी बेटी-बहुओं द्वारा किए गए घर के काम को वही तवज्जो देनी चाहिए जो हम लड़कों द्वारा किए गए काम को देते हैं. संतुलन तभी आएगा जब हम ये स्वीकार करेंगे कि रेडी टू ईट फूड अल्पकालिक समाधान हो सकता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ घर से बाहर जाकर काम कर सकें तो आपके लिए घर पर अच्छा खाना बनना ज़रूरी है. और खाना बनाना उतना ही ज़रूरी काम है जितना ज़रूरी बाहर जाकर काम करना है.

क्या है नौतपा? 9 दिन चरम पर होगी सूर्य की गर्मी, चंद्र की घटेगी शीतलता, जानें कब होगी शुरुआत?

ज्योतिषशास्त्र नुसार सूर्य शनिवार 25 मई को सुबह 03:15 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 2 जून रविवार तक नौ (9)दिन का नौतपा रहेगा. इसके साथ ही सूर्य देव 8 जून शनिवार को 1:04 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे इन दिनों गर्मी प्रचंड रहेगी व पारा 48 डिग्री के पार कर सकता है।

नौतपा है मानसून का गर्भकाल

मान्यता है कि सूर्य की गर्मी और रोहिणी नक्षत्र (जिसका स्वामी चंद्र है) के जल तत्व के कारण यह मानसून का (9 दिन मे) गर्भ आ जाता है और इसी कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है. ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस समय चंद्रमा नौ नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं।.

लोक मान्यता है कि अगर नौतपा के सभी 9 दिन पूरे तपें, तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है।. ज्योतिषों का कहना है कि चंद्रमा जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थितियों में हो और अधिक गर्मी पड़े, तो वह नौतपा अच्छा कहलाता है. वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है और उस दौरान अगर बारिश हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना (गर्भपात) भी कहा जाता है।

नौतपा 2024: देश में गर्मी अब अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है. कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि इस बार मई माह में नौतपा शुरू हो जाएगा. इन 9 दिनों की अवधि में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी और इस कारण सूर्यदेव की तपिश काफी ज्यादा महसूस होगी. जिससे इन दिनों गर्मी प्रचंड रहेगी व पारा 48 डिग्री के पार कर सकता है.।

8 जून शनिवार को1:05 मिनट सेही सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जायेंगे

जो भारत मै मानसून की शुरुआत होती है।(पहले यह तिथी 7 जून हुआ करती थी)

नौतपा में इन बातों का रखें ध्यान

नौतपा के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. ताकि शरीर में किसी तरह की परेशानी न हो. साथ ही राहगीरों और जरूरतमंदों को जल पिलाना चाहिए. मान्यता है कि यह एक प्रकार का पुण्य का कार्य है।.

गर्भवती महिलाए ,बिमार परिजन का खास ख्याल रखे ।

इसके अलावा मान्यता यह भी है कि नौतपा के दौरान प्यासे को जल पिलाने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है।.

नौतपा के दौरान सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. साथ ही समाज में मान-सम्मान भी बढ़ता है।

यदि आप आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है उसको मजबूत करना चाहते हैं तो नौतपा के दौरान रोजाना सुबह सूर्य देव की अराधना करें और अर्घ्य दें।

इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी लाभकारी होता है।

अपनी सभी प्रकार की यात्रा प्रकार,सफर,बाहर जाना कमसे कम 2 जुन तक टाले।

मतदान अधिकार का महत्व और युवाओं को वोट डालने की आवश्यकता

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मतदान है। यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को देश की शासन व्यवस्था में भागीदारी का अवसर देता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में, मतदान अधिकार का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि समाज की दिशा और भविष्य को भी निर्धारित करता है।

मतदान अधिकार का महत्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार: मतदान हर व्यक्ति को सरकार चुनने का अवसर देता है। यह एकमात्र तरीका है जिससे जनता अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते है और अपने विचारों को सरकार की नीतियों में बदल सकते है।

समानता और न्याय: मतदान सभी को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग से संबंधित हो। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए और उसका महत्व हो।

जवाबदेही: मतदान के माध्यम से नागरिक अपनी सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, तो मतदान के जरिए उसे बदलने का अवसर मिलता है।

सामाजिक परिवर्तन: इतिहास गवाह है कि मतदान के माध्यम से ही समाज में बड़े परिवर्तन आए हैं। चाहे वह सामाजिक न्याय हो, शिक्षा का अधिकार हो, या महिला सशक्तिकरण, सभी बड़े बदलावों की नींव मतदान के माध्यम से ही पड़ी है।

युवाओं को मतदान क्यों करना चाहिए?

भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवाओं का है। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, और इसलिए उनका मतदान में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है।

देश का भविष्य: युवा देश के भविष्य निर्माता हैं। उनका वोट देश की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवश्यक है कि वे इस जिम्मेदारी को समझें और सक्रिय रूप से मतदान करें।

नई सोच और दृष्टिकोण: युवा नई सोच और दृष्टिकोण लेकर आते हैं। उनकी भागीदारी से न केवल चुनाव प्रक्रिया में ताजगी आती है, बल्कि नई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश का विकास भी होता है।

स्वयं के हित: सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ सीधा युवाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और कई अन्य क्षेत्रों में निर्णय सीधे तौर पर युवाओं के हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए, युवाओं को अपने हितों की रक्षा के लिए मतदान करना चाहिए।

सक्रिय नागरिकता: मतदान के माध्यम से युवा एक सक्रिय नागरिक बन सकते हैं। यह उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है।

मतदान एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर युवाओं को यह समझना होगा कि उनका एक वोट देश की दिशा बदल सकता है। इसलिए, सभी युवा नागरिकों को चाहिए कि वे मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालें और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। केवल एक सक्रिय और जागरूक युवा ही देश को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है।

दिल्ली पुलिस के बेडे में 1427 नए कांस्टेबल हुए शामिल

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। राजधानी की दिल्ली पुलिस अकादमी वजीराबाद में पासिंग आउट परेड का आयोजन कर पुलिस बेडे में 1270 ड्राइवर, कांस्टेबल विधिवत शामिल हो गए। इसके अलावा 157 कांस्टेबल भी विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस मे शामिल हुए। यह अब-तक का सबसे बडा बैच ड्राइवर का माना जा रहा है। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग के दौरान न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही राजधानी पुलिस के भी गुर सिखाए गए है। डिप्टी डायरेक्टर-2 उमाशंकर के मुताबिक जो 157 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, उनमें 38 महिला शामिल है। आकादमी द्वारा आयोजित पासिंग आउट परेड में स्पेशल पुलिस कमिश्नर (एचआरडी) एसके गौतम ने परेड की सलामी ली। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस अकादमी के ज्वाइंट डायरेक्टर आसिफ मौहम्मद अली, के अलावा गुजरात के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के गेस्ट और दिल्ली पुलिस के कई सीनियर आफिसर भी मौजूद रहे। इन रंगरूटों में अलग-अलग राज्यों से शामिल है। इनमें 122 पोस्ट ग्रेजुएट है। 788 ग्रेजुएट है। जबकि टेक्निकल पढाई कर चुके कांस्टेबलों की संख्या 58 है। इन शामिल कांस्टेबल को नए कानून के अलावा राजधानी दिल्ली में लॉ एंड आर्डर मेंटेन करने के दौरान किन तरीके से काम किया जाता है। ट्रेफिक रूल्स, कम्प्यूटर के बारे एवं, किसी इमर्जेंसी की स्थित में फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। इस बारे में अलग से ज्ञान दिया गया है।

दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024

दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 छठे चरण यानी कल (25 मई 2024) को है। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने अब तक जो लिस्ट तैयार की है, उसमें कुल वोटरों की संख्या 1,47,18,119 है। दिल्ली में पुरुष वोटरों की संख्या 54.2% हैं। दिल्ली में 45.7% महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर वोटरों की कुल संख्या 1,176 है। सबसे अधिक थर्ड जेंडर वोटर्स साउथ दिल्ली और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हैं। 1176 थर्ड जेंडर वोटर्स में से साउथ दिल्ली में 339 और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 238 हैं। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में इनकी संख्या 100 से 170 के आसपास हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में महिला और पुरुष वोटरों के बीच सबसे कम अंतर है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वेस्ट दिल्ली है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या 24,88,831 हैं। यह वोटरों की संख्या में कुल वोटर्स के करीब 17 प्रतिशत है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र वोटरों के लिहाज से सबसे छोटा है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स 14,81,338 हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में अगामी लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले वोटरों की संख्या बढ़ी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के सातों सीटों के लिए वोटरों की संख्या 1,42,37,458 थी, जबकि वर्तमान में दिल्ली के सातों सीटों पर वोटरों की कुल संख्या 1,47,18,119 है। पिछले 5 साल में वोटरों की संख्या में करीब 3.37 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली में आज इनकी अग्नि परीक्षा: आठ उम्मीदवारों के सामने जीत तो पांच के समक्ष हार का सिलसिला तोड़ने की चुनौती

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की सातों सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की शनिवार को मतदान के लिए अलग-अलग मामलों में अग्नि परीक्षा होगी। दरअसल चार उम्मीदवारों ने अभी तक चुनावी दंगल में मात नहीं खाई है। इसके अलावा चार उम्मीदवार अपने पिछले एक से दो चुनाव जीते हैं। वहीं पांच उम्मीदवार अपने पिछले एक से लेकर तीन चुनाव हार चुके हैं। इनमें से दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक जीत का स्वाद नसीब नहीं हुआ है। इस तरह आठों उम्मीदवारों के समक्ष जीत का रथ आगे बढ़ाने और पांच उम्मीदवारों के समक्ष हार का सिलसिला खत्म करने की चुनौती है।

दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के 14 उम्मीदवारों में से छह को ही लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव है। इनमें शामिल चांदनी चौक क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल व उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज, उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी व पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। जबकि दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी व उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार इस मामले में कामयाब नहीं हुए हैं। कन्हैया कुमार ने अभी तक एक ही चुनाव लड़ा है और वे उसमें हार गए थे। उनकी भांति चांदनी चौक क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवीन खंडेलवाल को भी जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा व आप के कुलदीप कुमार, नई दिल्ली क्षेत्र से आप के सोमनाथ भारती व उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस के उदित राज अभी तक चुनाव में हारे नहीं हैं।

हार का सिलसिला खत्म करने की चुनौती

चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल का भाजपा के प्रवीन खंडेलवाल के साथ मुकाबला है। प्रवीन खंडेलवाल ने अभी तक एक मात्र चुनाव वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें वह हार गए थे। वहीं जयप्रकाश अग्रवाल को पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह इन दोनों उम्मीदवारों के समक्ष हार का सिलसिला खत्म करने की चुनौती है।

जीत का सिलसिला जारी रखने व हार का सिलसिला खत्म करने की चुनौती

पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा के सामने भाजपा की कमलजीत सहरावत चुनाव लड़ रही हैं। वह वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन वह एमसीडी के पिछले दोनों चुनाव में जीती। हालांकि लगातार पांच बार (एक बार पार्षद, तीन बार विधायक व एक बार सांसद) चुनाव जीतने वाले महाबल मिश्रा को पिछले दोनों लोकसभा चुनाव व वर्ष 2015 में विधानसभा में चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उदित राज ने वर्ष 2014 में इस क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा था और इसमें वह भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के योगेंद्र चांदोलिया से है। चांदोलिया लगातार तीन बार एमसीडी चुनाव जीत चुके हैं, मगर पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से मनोज तिवारी पिछले दोनों चुनाव जीते हैं, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार कन्हैया कुमार लड़े एक मात्र चुनाव हार गए थे। इस तरह इन उम्मीदवारों के समक्ष जीत का सिलसिला जारी रखने व हार का सिलसिला खत्म करने की चुनौती है।

एक की जीत का सिलसिला टूटना निश्चित

पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वह अभी तक चुनाव में हारे नहीं हैं। इस बार उनका आमना-सामना होने के कारण एक की जीत का सिलसिला टूटना निश्चित माना जा रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने एक मात्र वर्ष 2012 में एमसीडी चुनाव लड़ा है। वहीं कुलदीप कुमार ने वर्ष 2017 में एमसीडी व 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था।

बांसुरी के समक्ष जीत के साथ राजनीतिक जीवन शुरू करने की चुनौती

नई दिल्ली क्षेत्र से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती लगातार तीन बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा की बांसुरी स्वराज के साथ है। बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लिहाजा भारती के समक्ष जीत का सिलसिला जारी रखने व बांसुरी के समक्ष जीत के साथ राजनीतिक जीवन शुरू करने की चुनौती है।

दक्षिणी दिल्ली में दोनों उम्मीदवारों के समक्ष जीत का सिलसिला जारी रखने की चुनौती

दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कई चुनाव लड़े हैं और उनका हार-जीत के मामले में मिलाजुला परिणाम रहा है। हालांकि वह पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आप के सहीराम पार्षद व विधायक के कई चुनाव जीत चुके हैं। वह हारे भी हैं, मगर पिछले दोनों विधानसभा चुनाव जीते हैं। इस तरह इन दोनों के समक्ष जीत का सिलसिला जारी रखने की चुनौती है।

जब भी बढ़ी सूरज की तपिश, दिल्ली में कम हुआ मतदान; दो लोकसभा चुनाव में दिख चुका है असर

दिल्ली में नौ लोकसभा चुनावों में मतदान राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। ऐसे में इस बार दिल्ली में मतदान बढ़ा पाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मतदान के दौरान भीषण गर्मी होने के आसार हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। राजधानी में जब-जब तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो मतदान फीसदी में गिरावट आई है। दिल्ली में नौ लोकसभा चुनावों में मतदान राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। ऐसे में इस बार दिल्ली में मतदान बढ़ा पाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मतदान के दौरान भीषण गर्मी होने के आसार हैं। हालांकि, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी।

दिल्ली में मई में जब भी चुनाव हुए तो मतदान कम हुआ। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 अप्रैल को मतदान हुआ था तो 65.10 प्रतिशत रहा था। बीते लोकसभा चुनाव में 12 मई को मतदान हुआ था तो दिल्ली में 60.6 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो वर्ष 2019 के मुकाबले साढ़े चार प्रतिशत कम था। इसके पहले मई में हुए चुनावों में मतदान और भी कम रहा था। इस बार दिल्ली में 25 मई को मतदान है और बीते चुनाव के मुकाबले 7 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहने के आसार हैं।

46 के पार पहुंच सकता है तापमान

दिल्ली में शुक्रवार से लू चलने से लोग घरों से निकलने में बच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई को सफदरजंग इलाके में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं, पीतमपुरा, नजफगढ़, पूसा आदि में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल, पंखे, बैठने के लिए बेंच, शेल्टर, शेड आदि का इंतजाम किया गया है। मतदान केंद्र से घर तक जाने के लिए मुफ्त में बाइक टैक्सी का भी इंतजाम किया गया है।

गर्मी से बचने के लिए व्यापक उपाय

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों और मौसम विभाग के 44-45 डिग्री तापमान और लू की चेतावनी के अनुसार व्यापक कदम उठाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर छायादार क्षेत्र बनाए गए हैं जहां ठंडक के लिए कूलर और पंखे लगे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने के पानी, शौचालय, रैंप और व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है।

हाईटेक प्रचार में जुटेंगे उम्मीदवार

उम्मीदवारों ने हाईटेक अंदाज में मतदाताओं से अपील करने का फैसला किया है। वे क्षेत्र के मतदाताओं से सोशल मीडिया, मोबाइल फोन आदि माध्यमों से संपर्क साधेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मतदाता पर्ची बांटने के बहाने लोगों से संपर्क साधने को कहा है। उम्मीदवारों ने इलाके के प्रमुख लोगों के घरों पर जाने की योजना बनाई है। चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवारों को किसी भी मतदाता के घर जाने की मनाही नहीं है। उम्मीदवार अकेले जा सकते हैं। वे अपने साथ लोगों व गाड़ियों का काफिला नहीं रख सकते।

दिल्ली में पहली बार मतदान के दिन ड्रोन का होगा इस्तेमाल

शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस इस बार ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। ऐसा पहली बार होगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्रोन की तैनाती होगी। पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद 50 से ज्यादा ड्रोन खरीदे या किराए पर लिए हैं। इनसे दिल्ली में 429 संवेदनशील बूथों पर नजर रखी जाएगी। एक ड्रोन से 12 से 14 बूथों पर नजर रखी जा सकेगी। उत्तर-दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम को 5 बजे से पुलिस पोलिंग बूथों की सुरक्षा संभाल लेगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा खुद हर इलाके का जायजा लेते रहेंगे। करीब 33 हजार पुलिसकर्मी पोलिंग बूथों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। करीब नौ से दस हजार पुलिसकर्मी पिकेट चेकिंग व कानून व्यवस्था को संभालेंगे। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश व यूपी से 17500 होमगार्ड बुलाए गए हैं। अर्द्धसैनिक बलों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जाएगी।

लोकसभा चुनाव के लिए 13600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से दिल्ली पुलिस ने 460 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित किए हैं। उत्तर-पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा करीब 45 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इनमें से करीब 20 को बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील मतदान केंद्र माना गया है।

एनडीएमसी ने बनाए 10 पिंक बूथ और सेल्फी प्वाइंट

एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में मतदान करने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस कड़ी में उसने थीम आधारित मतदान केंद्र बनाए है। इनमें मतदाता विशेष अनुभव के साथ अपना वोट डालेंगे। क्षेत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नेता आदि आम जनता के साथ वोट डालेंगे। एनडीएमसी के 10 मतदान केंद्रों पर थीम आधारित विशेष व्यवस्था की है। इनको फूलों की सजावट के साथ पिंक बूथ बनाया है। मतदान केंद्रों में हरित वातावरण, मतदाताओं के लिए सेल्फी प्वाइंट, बूथ स्थानों पर गमले में पौधे, वेटिंग हॉल में ग्लूकोज के साथ मटका पानी की व्यवस्था, मॉडल मतदान केंद्रों पर हरा प्रवेश द्वार आदि व्यवस्था होगी।

मतदान केंद्रों के स्वच्छ हरित थीम, हरित गतिशीलता व पानी बचाएं की थीम, लोकतंत्र की शक्ति थीम के साथ गुलाबी मतदान केंद्र और यंग थीम आधारित मतदान केंद्र भी विशेष व्यवस्था में शामिल है।

दिल्लीवासियों के लिए जरूरी खबर, वोटिंग से पहले Delhi-NCR के मतदाताओं से चुनाव आयोग ने की ये खास अपील

चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े शहरों में मतदाताओं व युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली गुरुग्राम व फरीदाबाद के मतदाता मतदान के प्रति इस शहरी उदासीनता को तोड़ें। आयोग ने कुछ समय पहले सभी बड़े शहरों के जिलाधिकारियों को मतदान बढ़ाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया था। तीसरे चरण में भी कुछ महानगरों में मतदान के स्तर से निराशा हुई।

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में मौजूद हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के मतदाता चुनाव में शहरी उदासीनता की प्रवृति को छोड़कर शनिवार को होने वाले छठे चरण के मतदान में अधिक से अधिक मतदान करें। आयोग ने युवाओं से अपील कि है कि वे बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि 20 मई को पांचवें चरण के मतदान में मुंबई, ठाणे, नासिक व लखनऊ जैसे महानगरों में वर्ष 2019 जैसा ही शहरी उदासीनता की प्रवृति देखी गई। इस वजह से उन शहरों में मतदान कम हुआ। तीसरे चरण के मतदान में भी कुछ महानगरों में मतदान के स्तर से निराशा हुई।

युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता बड़ी चिंता

बड़े शहरों में मतदाताओं व युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली, गुरुग्राम व फरीदाबाद के मतदाता मतदान के प्रति इस शहरी उदासीनता को तोड़ें। आयोग ने कुछ समय पहले सभी बड़े शहरों के जिलाधिकारियों को मतदान बढ़ाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया था।

चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, तैनात रहेंगे साढ़े चार हजार पुलिसकर्मी; CCTV से होगी निगरानी

मतदान को लेकर गुरुवार को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने जिले के सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि शांतिपूर्वक व निष्पक्ष मतदान के लिए गुरुग्राम पुलिस की ओर से समुचित संख्या में पुलिस कर्मियों को डयूटी पर लगाया गया है। इनमें बूथ ड्यूटी पेट्रोलिंग पार्टी नाकाबंदी फ्लाइंग स्क्वाड सेक्टर आफिसर जोनल मजिस्ट्रेट सर्विलांस टीम आदि के साथ लगाए गए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। छठे चरण में गुड़गांव लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान होगा। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गुरुग्राम जिले में कुल 537 स्थानों पर कुल 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 79 स्थानों पर 201 संवेदनशील बूथ भी शामिल हैं। इन सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन बूथों पर लगभग 4500 पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं।सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों व राज्यों से लगती हुई सीमा पर नाकाबंदी की गई है।

मतदान को लेकर गुरुवार को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने जिले के सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि शांतिपूर्वक व निष्पक्ष मतदान के लिए गुरुग्राम पुलिस की ओर से समुचित संख्या में पुलिस कर्मियों को डयूटी पर लगाया गया है। इनमें बूथ ड्यूटी, पेट्रोलिंग पार्टी, नाकाबंदी, फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्टर आफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, सर्विलांस टीम आदि के साथ लगाए गए हैं।

होम गार्ड के भी जवान अलाट हुए हैं। मतदान के दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने एरिया में फोर्स सहित मौजूद रहेंगे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। पुलिस का प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को बाधित या खराब ना करने पाए तथा किसी भी बूथ पर पुनः मतदान की नौबत ना आने पाए।

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर शुरू की चेकिंग

मतदान के दौरान क्राइम यूनिटों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान आठ इंटर-स्टेट व 27 इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाकों सहित कुल 35 पुलिस नाके लगाए गए हैं। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले के सभी बार्डर एरिया कापड़ीवास, सिरहौल समेत अन्य जगहों पर पुलिस ने बेरिकेडिंग कर आने-जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त 85 सेक्टर आफिसर व 85 सेक्टर पुलिस आफिसर को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जिले के सभी 1333 बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले के 500 बूथों पर सुगम मतदान के लिए एनसीसी वालंटियर्स की भी सेवाएं ली जाएंगी।

पुलिस अधिकारी निकाल रहे फ्लैग मार्च

जिले में 113 संवेदनशील पोलिंग बूथों पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ ही सीएपीएफ की छह टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। शुक्रवार शाम तक सीएपीएफ की सभी छह टुकड़ियां गुरुग्राम आ जाएंगी। स्ट्रांग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में गार्ड व निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

समन्वय स्थापित करने के लिए निकाला फ्लैग मार्च

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते गुरुग्राम के पूर्व पुलिस जोन के एरिया में गुरुग्राम पुलिस व सीएपीएफ की टुकड़ियों ने सुरक्षा और समन्वय स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर-52, थाना सेक्टर-53, वजीराबाद रेड लाइट, सेक्टर 56, घाटा टी-प्वाइंट, डीएलएफ फेज एक, नीलकंठ अस्पताल, डीएलएफ फेज तीन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, डीएलएफ सेक्टर 29, हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो, सुशांत लोक, कन्हई रेड लाइट, सेक्टर-40 के एरिया में फ्लैग मार्च किया गया।

अनियंत्रित होकर नाले में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, दो किसान की मौत, घटना में एक घायल

मोदीनगर (Modinagar Road Accident) के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव हृदयपुर भंडौला में एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। इस हादसे में दो किसान की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि तीसरा इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

नोएडा। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव हृदयपुर भंडौला में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली नाले में पलट गई। हादसे में किसान उपेंद्र व विनय की मौत हो गई। जबकि, ट्राली में बैठे चंद्रबली गंभीर रूप से घायल हो गये। तीनों खेत में ईंख का बीज रखकर दूसरे खेत पर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजे हैं।

पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच

हादसे के कारणों की जांच में पुलिस (Ghaziabad Police) जुटी है। शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं। मौत की सूचना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। हृदयपुर भंडौला गांव के विनोद कुमार का गांव में ही खेत हैं। जिस पर गांव के ही उपेंद्र, विनय व चंद्रबली काम करते थे। बृहस्पतिवार को तीनों खेत पर ईंख की बीज रखने गए थे। विनोद के एक खेत पर बोआई चल रही थी।

नाले में गिरते ही ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग

वहां बीज रखने के बाद विनोद के दूसरे खेत पर ट्रैक्टर-ट्राली से जा रहे थे। ट्रैक्टर उपेंद्र चला रहे थे। पीछे ट्राली में गन्ने के बीज के साथ चंद्रबली बैठे थे। खेत से थोड़ी ही दूरी पर जब वे पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। उपेंद्र ने संभालने की कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर पास से गुजर रहे नाले में पलट गया। नाले में गिरते ही ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग हो गई।

डॉक्टरों ने उपेंद्र और विनय को किया मृत घोषित

आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़े तो नाले से तीनों को निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उपेंद्र व विनय को मृत घोषित कर दिया। जबकि चंद्रबली को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर व ट्रॉली को बाहर निकलवाया गया।

हादसे की सूचना पर गांव से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल रहा। आसपास के लोगों ने उनको ढांढस बंधाया। गांव में एक साथ हुई दो मौत से मातम का माहौल है। दोनों मृतक के घर भी आसपास में ही हैं।

दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। काफी समय से दोनों एक-साथ काम कर रहे थे। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि दोनों के शव पोस्टमार्टम को भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है।

सुबह से ही लगने लगी सेक्टर-14 में पोलिंग पार्टियों की भीड़, EVM लेकर हुईं रवाना

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण यानी 25 मई के मतदान के लिए अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव है, वहां पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रही हैं। यही हाल हरियाणा के गुरुग्राम में भी है, जहां पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए कूच करना शुरू कर चुकी हैं।

गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लिए शनिवार को होने वाले मतदान को लेकर सेक्टर-14 स्थित कॉलेज में पोलिंग पार्टियों का जमावड़ा लगा है।

यहां से ईवीएम आदि सामान लेकर पार्टियां सेक्टर-14 गर्ल्स कॉलेज से बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना और पटौदी क्षेत्र के लिए रवाना हो रही हैं।

गुरुग्राम जिले में बनाए गए हैं कुल 1333 मतदान केंद्र

गुरुग्राम जिले में कुल 537 स्थानों पर कुल 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 79 स्थानों पर 201 संवेदनशील/क्रिटिकल बूथ भी शामिल हैं। इन सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन बूथों पर लगभग 4500 पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

सुरक्षा के ऐसे हैं इंतजाम

चिन्हित किए गए सभी 201 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा बल, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं।

चुनावों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों व राज्यों से लगती हुई सीमा पर नाकाबंदी भी की गई है। एरिया के सम्बन्धित डीसीपी, एसएसपी, एसएचओ के अतिरिक्त कई पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं।

7 हजार कर्मचारी कराएंगे मतदान

7 हजार कर्मचारी करवाएंगे मतदान। 19 क्यूआरटी टीम, 12 एसएसटी, 20 एफएसटी फील्ड में तैनात किए गए हैं।

गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कुल 25.73 लाख मतदाता हैं, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर-14 कॉलेज में बसों की व्यवस्था की गई है।

पावर ग्रिड के प्रबंधक से शेयर में निवेश के नाम पर 39 लाख रुपये की ठगी

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधक से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा देकर करीब 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। प्रबंधक की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

गुरुग्राम। पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधक से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा देकर करीब 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। प्रबंधक की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सेक्टर 43 की पावरग्रिड टाउनशिप निवासी वेंकटेश गोरली मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके व्हाट्सएप पर एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया था।

मोटा मुनाफा कमाने का दिया था लालच

इसमें कैपिटल इंडिया के शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। जब बातचीत शुरू हुई तब साइबर ठगों ने उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया। इसके बाद उनसे शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए जमा कर लिए गए। उन्हें ऑनलाइन एप पर बड़ा मुनाफा दिखाया गया।

उन्होंने करीब 13 लाख रुपये शुरुआत में जमा किए थे। मुनाफा होने के बाद रुपए निकालने के लिए जब उन्होंने कोशिश की, तब उनसे सिक्योरिटी मनी के रूप में रुपए मांगे गए। कई बार में उनसे 38 लाख 87 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। रुपये वापस न मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ममता सरकार संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर से नहीं

भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानून की कितनी ही धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़ी। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है।

योगेन्द्र योगी

पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानून की कितनी ही धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़ी। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर भी केंद्र की भाजपा सरकार की खिलाफत की है। कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हाइकमान ने भी कभी ऐसे आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर नहीं लगाए, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं। ममता ने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, राजनीतिक आधार पर बंदरबाट जैसे मुद्दों पर अदालतों से जितनी फटकार खाई है, उतनी देश के किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं खाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिमी बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को अदालत द्वारा रद्द करने का है। इस आदेश को सदाशयता से मान कर अपील करने की दलील देने के बजाए मुख्यमंत्री ममता ने ही फैसला देने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा दिया। ऐसा करके ममता ने बगैर किसी भय के सरेआम अदालत की अवमानना कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी, जो तपशिली समुदाय को दिए गए अधिकार छीन लेगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस प्रशासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाणपत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि, इससे वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या सीटें रखने वाले या जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5 फीसदी ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1 फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन, 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थीं। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92 फीसदी मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा।

हाईकोर्ट ने ओबीसी के मामले में सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद तो मानो ममता का पारा उछल गया। ममता ने अदालत पर मनमाने आरोप लगा दिए। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो जाता है... आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुश्री बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि अदालत का फैसला तपशिली समुदाय के लिए आरक्षण रद्द करने के भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है। ममता के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि ममता जी ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं - क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दे? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वेक्षण के 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया। कोई अदालत में चला गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटना चाहती हैं और मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो फैसले हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी।

ममता बनर्जी ने वोटों के धुवीकरण की राजनीति करने में कसर बाकी नहीं रखी। मुद्दा चाहे रामनवमी पर हिंसा का हो या संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं के साथ अत्याचारों का। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट बैंक को रिझाने के लिए उल्टे भाजपा और दूसरे विपक्षी दलों पर ही निशाने साधे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के मौजूदा और पूर्व कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का ताडंव जम कर हुआ। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग खुलासे, कोयला और मवेशी तस्करी, राशन घोटाले और सरकारी परियोजनाओं के लिए फंड से लिए गए कट मनी के आरोपों के बावजूद ममता सरकार में कोई सुधार नहीं दिखा। इससे जाहिर है कि ममता बनर्जी मनमानी करने पर आमदा हैं।

बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला व राशन वितरण घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक नेता मंत्री सलाखों के पीछे हैं। इनमें पूर्व मंत्री व विधायक पार्थ चटर्जी, विधायक अनुब्रत मंडल, विधायक मानिक भट्टाचार्य, विधायक जिबनकृष्ण साहा प्रमुख हैं। इस कड़ी में वन मंत्री व पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का नाम जुड़ गया है। करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य सृंजय बोस और तृणमूल के विधायक और तत्कालीन परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार किया गया था। मित्रा और बोस दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल पुलिस ने शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी के प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। ममता सरकार की सर्वाधिक किरकिरी संदेशखाली की शर्मनाक वारदात में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कैसे संपर्क कर सकती है? जहां तक वोटों की राजनीति और बहुमत पाने से काले कारनामों के धुल जाने का सवाल है तो लालू यादव बहुमत के बावजूद जेल गए थे। लोकतंत्र में कानून से खिलवाड़ करने के लिए बहुमत को आधार नहीं माना जा सकता। ममता बनर्जी को इससे सबक लेना चाहिए।

ये अफोर्डेबल एसयूवी देती हैं बेहतरीन माइलेज, कीमत भी 10 लाख रुपये से कम

परिवहन विशेष न्यूज

मारुती सेलेरिओ इंडियन मार्केट में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी अन्य पेट्रोल कारों में सबसे ऊपर है। मारुति एस-प्रेसो ऑटोमैटिक वेरिएंट में 25.3 kmpl और मैनुअल वेरिएंट में 24.76 kmpl तक का माइलेज दे सकती है। नई जनरेशन की स्विफ्ट हैचबैक को नए इंजन के साथ लॉन्च किया गया है जो पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में अधिक फ्यूल एफिशियंसी का वादा करती है।

नई दिल्ली। भारतीय ग्राहक नई कार खरीदते समय सबसे पहले उसकी फ्यूल एफिशियंसी चेक करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कार निर्माता भी इंजनों को अपग्रेड कर रहे हैं और उन्हें इस तरह से ट्यून किया है कि वे ईंधन पर खर्च किए गए पैसे का सबसे अच्छा संभव मूल्य प्रदान करें। आइए, उन पेट्रोल इंजन वाली कारों पर नजर डाल लेते हैं, जो बेहतरीन माइलेज प्रदान करती हैं। इनकी कीमतें भी 10 लाख रुपये से कम हैं।

Maruti Celerio

Maruti Celerio इंडियन मार्केट में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी अन्य पेट्रोल कारों में सबसे ऊपर है। 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित सेलेरियो मैनुअल वेरिएंट में 25.24 kmpl तक का ARAI-क्लेम्ड माइलेज देती है।

इस हैचबैक का ऑटोमैटिक वेरिएंट 26.68 kmpl तक की बेहतर फ्यूल एफिशियंसी प्रदान करता है। सेलेरियो को इंडियन मार्केट में 5.36 लाख रुपये से लेकर 7.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेच रही है।

Maruti S-Presso

मारुति एस-प्रेसो की प्रमाणित फ्यूल एफिशियंसी अन्य कारों की तुलना में अधिक है। 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस यह कार ऑटोमैटिक वेरिएंट में 25.3 kmpl और मैनुअल वेरिएंट में 24.76 kmpl तक का माइलेज दे सकती है। एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 4.26 लाख रुपये है। टॉप वेरिएंट की कीमत 6.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Maruti Alto K10

ऑल्टो K10 हैचबैक ARAI के आंकड़ों के अनुसार ऑटोमैटिक पेट्रोल वेरिएंट में 24.9 kmpl का माइलेज देती है। वहीं, मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट 24.39 kmpl का माइलेज देता है। 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस, मारुति ऑल्टो K10 को 4 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Maruti WagonR

मारुति की यह बॉक्सी हैचबैक 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा छोटा इंजन ARAI द्वारा प्रमाणित 24.35 kmpl की माइलेज देता है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट 25.19 kmpl तक की माइलेज देता है। बड़ा इंजन भी काफी किफायती है और इसका माइलेज 23.9 kmpl तक है। वैगनआर की कीमत 5.54 लाख रुपये से 8.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

Maruti Swift

मारुति सुजुकी ने हाल ही में नई जनरेशन की स्विफ्ट हैचबैक को नए इंजन के साथ लॉन्च किया है, जो पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में अधिक फ्यूल एफिशियंसी का वादा करती है। ARAI के आंकड़ों के अनुसार, नई स्विफ्ट का ऑटोमैटिक वेरिएंट 25.75 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि मैनुअल वेरिएंट 24.8 kmpl तक का माइलेज देता है। 2024 स्विफ्ट में नया 1.2-लीटर K सीरीज, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 6.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

एम एस धोनी बने सिट्रोएन के ब्रांड एंबेसडर, कंपनी को मिलेगी अब नई पहचान

Citroen ने शुक्रवार को कहा कि उसने पूर्व भारतीय क्रिकेटेर Mahendra Singh Dhoni को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड निदेशक शिशिर मिश्रा ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक धोनी के साथ हमारा जुड़ाव भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

नई दिल्ली। फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी Citroen ने शुक्रवार को कहा कि उसने पूर्व भारतीय क्रिकेटेर Mahendra Singh Dhoni को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि धोनी सिट्रोएन के साथ अपनी पहली पारी की शुरुआत एक अभियान में करेंगे जो जल्द ही लाइव होगा।

कंपनी ने क्या कहा?

सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड निदेशक शिशिर मिश्रा ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक धोनी के साथ हमारा जुड़ाव भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उत्कृष्टता के प्रति उनकी विनम्रता और समर्पण हमारे ब्रांड की विचारधारा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जबकि स्थिरता और गतिशीलता के भविष्य को आकार देने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारे संबंध को मजबूत करती है।

MS Dhoni ये बोले

सिट्रोएन के साथ अपने जुड़ाव पर धोनी ने कहा कि ब्रांड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टिकाऊ समाधानों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को साझा करता है और मेरी तरह, वास्तव में जो मायने रखता है उसे करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्राहकों की जरूरतों को सही मायने में समझने और सार्थक इनोवेशन करने की सिट्रोएन की फिलॉसफी मेरे साथ गहराई से जुड़ती है।

गर्मियों में कर रहे हैं माउंटेन ट्रिप की तैयारी, तो इन जरूरी चीजों का रखें ध्यान

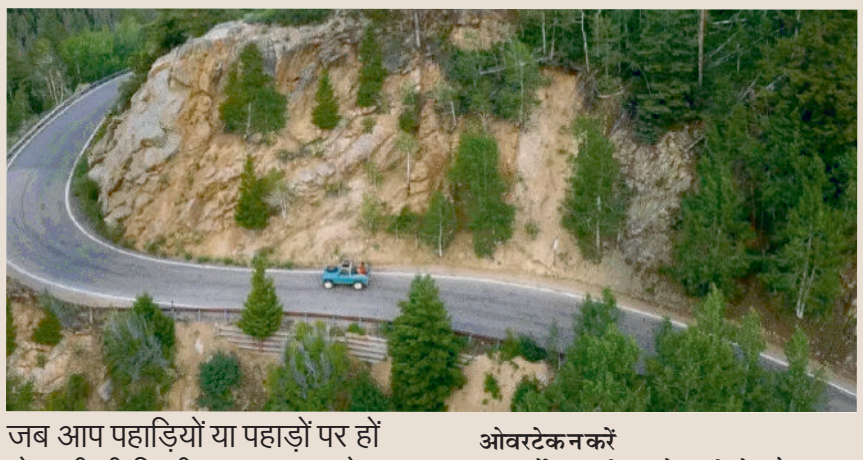

जब आप पहाड़ियों या पहाड़ों पर हों तो कभी भी किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश न करें। इसके अलावा पहाड़ी सड़कों पर धीमी गति से गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गियर शिफ्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रेविटी वाहन के विरुद्ध काम करती है जिससे वाहन धीमा हो जाता है।

नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा जैसे व्यस्त शहरों में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में वीकेंड और छुट्टियों होते ही कई लोग पहाड़ों पर निकल जाते हैं। लोग न केवल भीषण गर्मी में झुलसने के बाद ठंडक पाने के लिए, बल्कि ताजी हवा में सांस लेने औ प्राकृतिक सुंदरता को देखने लिए हिल स्टेशन की ओर रुख करते हैं।

हालांकि, ऐसी जगह कार ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए, पहाड़ियों पर ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखने वाले जरूरी टिप्स जान लेते हैं।

ओवरटेक न करें

राजमार्गों या शहरी सड़कों पर भी ओवरटेक करना काफी आसान है। जब आप पहाड़ियों या पहाड़ों पर हों, तो कभी भी किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है। पहाड़ी सड़कें संकरी होती हैं और उनमें मुश्किल और हेयरपिन मोड़ होते हैं, ऐसी सड़कों पर ओवरटेक करने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।

ड्राइविंग का ध्यान रखें

पहाड़ी सड़कों पर धीमी गति से गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। स्लो स्पीड में ड्राइविंग करने से आप गाड़ी से कंट्रोल नहीं खोएंगे। साथ ही आप सड़क और आस-पास के माहौल का भी थोड़ा आनंद ले पाएंगे।

सही गियर में गाड़ी चलाएं

पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गियर शिफ्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रेविटी वाहन के विरुद्ध काम करती है, जिससे वाहन धीमा हो जाता है। इसलिए, कम गियर में गाड़ी चलाएं जहां टॉर्क आउटपुट अधिकतम होगा। उतरते समय पहले या दूसरे गियर में गाड़ी चलाएं, क्योंकि कम गियर में गाड़ी चलाने से यह सुनिश्चित होगा कि वाहन की गति नहीं बढ़ेगी और नियंत्रण नहीं खोएगा।

जीप मेरिडियन फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान फिर आई नजर, लेवल-2 एडास के साथ मिलेंगे ये डिजाइन अपडेट

Jeep Meridian facelift के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें नए एलईडी हेडलैंप इनवर्टेड एल-शेप्ड एलईडी डीआरएल रिवाइज्ड ग्रिल और सिल्वर एक्सेंट के साथ ट्वीक्ड फ्रंट बंपर जैसे बदलाव किए जा सकते हैं। स्पाई शॉट में एसयूवी के इंटीरियर को भी दिखाई दे रहा है। पावरट्रेन की बात करें तो जीप मेरिडियन फेसलिफ्ट में 2.0-लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा।

नई दिल्ली। Jeep India आने वाले महीनों में भारतीय बाजार के अंदर Meridian facelift को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इस थ्री-रो वाली इस एसयूवी को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिसमें कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Jeep Meridian facelift के एक्सटीरियर की बात करें, तो इसमें नए एलईडी हेडलैंप, इनवर्टेड एल-शेप्ड एलईडी डीआरएल, रिवाइज्ड ग्रिल और सिल्वर एक्सेंट के साथ ट्वीक्ड फ्रंट बंपर जैसे बदलाव किए गए हैं। ऐसा स्पाई शॉट्स में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एसयूवी में रडार मॉड्यूल भी है और इसे बंपर पर रखा गया है। साथ ही अपडेटेड मॉडल लेवल 2 ADAS तकनीक के साथ आने की उम्मीद है। अन्य एक्सटीरियर बदलावों में एलॉय व्हील्स का नया सेट, इनवर्टेड एल-शेप्ड टेल लैंप, रिवाइज्ड रियर बंपर और बहुत कुछ शामिल होने की संभावना है।

इंटीरियर और फीचर्स

स्पाई शॉट में एसयूवी के इंटीरियर को भी दिखाई दे रहा है। मौजूदा जनरेशन मॉडल की तरह ही, मेरिडियन फेसलिफ्ट में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे कई अन्य फीचर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इसमें अपडेटेड अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड एयरकॉन वेंट्स, एयर प्यूरीफायर, रियर विंडो शेड्स और फ्रंट और रियर डैश कैमरा जैसे बदलावों के साथ नया केबिन थीम मिलेगा।

इंजन और परफॉरमेंस

पावरट्रेन की बात करें तो, जीप मेरिडियन फेसलिफ्ट में 2.0-लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो 170 hp की पीक पावर और 350 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करेगा। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा।

जीप मेरिडियन फेसलिफ्ट को 4WD सिस्टम के साथ भी पेश किया जाएगा, जो चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध होगा। मेरिडियन फेसलिफ्ट में संभवतः चार फ्रंट पार्किंग सेंसर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और फॉरवर्ड कोलिजन ब्रेकिंग के साथ रडार कैमरा होगा।

रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की अब भारत में होगी मैन्युफैक्चरिंग, कीमतों में हो सकती है इतनी कटौती

परिवहन विशेष न्यूज

Range Rover और Range Rover Sport का देश में स्थानीय रूप से निर्माण किया जाएगा। जगुआर लैंड रोवर पहले से ही देश में चार मॉडल - एफ-पेस डिस्कवरी स्पोर्ट इवोक और वेलार का निर्माण कर रहा है। लेकिन अब ध्यान रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट पर भी होगा जो ब्रांड के उत्पाद पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हैं। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Jaguar Land Rover ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि उसकी दो सबसे ज्यादा मांग वाली एसयूवी - Range Rover और Range Rover Sport का देश में स्थानीय रूप से निर्माण किया जाएगा।

यूके के बाद अब भारत में प्रोडक्शन

पुणे में कंपनी की फैसिलिटी में निर्मित होने के साथ, भारत यूके के बाहर पहला देश बन गया है, जहां इन मॉडलों का उत्पादन किया जाएगा। स्थानीय रूप से निर्मित एसयूवी की डिलीवरी आज से ही शुरू हो जाएगी। जेएलआर का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में इसने देश में प्रभावशाली बिक्री वृद्धि दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है।

सभी मॉडल के प्राइस

स्थानीय रूप से निर्मित रेंज रोवर 3.0-लीटर एचएसई एलडब्ल्यूबी की कीमत 2.36 करोड़ रुपये होगी, जबकि रेंज रोवर 3.0-लीटर पेट्रोल ऑटोबायोग्राफी वर्जन की कीमत 2.60 करोड़ रुपये (Before Tax) है। रेंज रोवर स्पोर्ट की कीमत डीजल और पेट्रोल दोनों संस्करणों के लिए 1.40 करोड़ रुपये (Before Tax) है।

स्थानीय उत्पादन से संबंधित घोषणा कंपनी ने यहां रेंज रोवर हाउस के आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर की, जो भारत में ब्रांड का पहला ऐसा अनुभवात्मक केंद्र है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि दोनों एसयूवी का स्थानीय रूप से उत्पादन करने का निर्णय इन कार मॉडलों की बढ़ती लोकप्रियता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

जेएलआर के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी लेनार्ड हूर्निक ने कहा-"पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्थिर और शानदार आर्थिक विकास देखा है और भविष्य में भी लगातार विकास करने की ओर अग्रसर है। इस विकास के परिणामस्वरूप समझदार भारतीय ग्राहकों के लिए उत्पाद पेशकशों को स्थानीय बनाने के जबरदस्त अवसर मिले हैं।"

JLR के प्रोडक्ट्स

जगुआर लैंड रोवर पहले से ही देश में चार मॉडल - एफ-पेस, डिस्कवरी स्पोर्ट, इवोक और वेलार का निर्माण कर रहा है। लेकिन अब ध्यान रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट पर भी होगा, जो ब्रांड के उत्पाद पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हैं। दोनों मॉडलों का उत्पादन 1970 से यूके के सोलीहुल में पहले से हो रहा है।

किआ सेल्टोस का बेस एचटीई वेरिएंट अब 5 नए कलर ऑप्शन में होगा उपलब्ध, जानिए कीमत और खासियत

नई दिल्ली। कोरियाई ऑटो दिग्गज Kia ने अपनी Seltos फ्लैगशिप एसयूवी के बेस वेरिएंट को नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। इसका HTE वेरिएंट 10.90 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में उपलब्ध है और अब ग्राहक इसे 5 एक्सटीरियर कलर में खरीद सकते हैं।

HTE वेरिएंट को मिले नए कलर ऑप्शन

इस वेरिएंट को पहले केवल दो एक्सटीरियर कलर विकल्पों के साथ पेश किया गया था, जिसमें क्लियर व्हाइट और स्पार्कलिंग सिल्वर शामिल थे। नए अपडेट के बाद सेल्टोस एसयूवी का बेस वेरिएंट अब 7 एक्सटीरियर कलर विकल्पों में उपलब्ध है। किआ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सेल्टोस का HTE वेरिएंट अब एक व्यापक पैलेट के साथ आता है जिसमें नया प्यूटर ऑलिव शेड भी शामिल है।

इस वेरिएंट में जोड़े गए चार अन्य नए रंग विकल्प इंपीरियल ब्लू, इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे और ऑरोरा ब्लैक पर्ल हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में केवल सिंगल-टोन कलर विकल्प मिलते हैं। डुअल-टोन सेल्टोस GTX+ वेरिएंट से शुरू होता है। टॉप-एंड X-लाइन वेरिएंट को विशेष रूप से मैटे ग्रेफाइट रंग मिलता है।

इंजन और परफॉरमेंस

किआ सेल्टोस एसयूवी का बेस HTE वेरिएंट 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह 113 बीएचपी की पावर और 144 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। किआ का दावा है कि यह वेरिएंट 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।

फीचर्स और इंटीरियर

फीचर्स के मामले में सेल्टोस बेस वेरिएंट में डिजिटल स्क्रीन के बजाय ड्राइवर डिस्प्ले के रूप में 4.2-इंच का कलर TFT और हायर वेरिएंट में पेश की गई नई LED हेडलाइट और DRL यूनिट के बजाय हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। हालांकि, सुरक्षा के मामले में किआ सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग प्रदान करता है। बेस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट सहित कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राजनीति

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डा. हेडगेवार के समय से लेकर डा. मोहन भागवत तक के काल में देश के इन्हीं सामाजिक-सांस्कृतिक मसलों से बावस्ता रहा है और प्रयास करता रहा है कि देश की राजनीति देश की समाज रचना और संस्कृति के केन्द्र बिन्दु के इर्द-गिर्द निर्मित होनी चाहिए'

संघ का देश की राजनीति से क्या संबंध है, यह प्रश्न प्रथम सरसंघचालक डा. हेडगेवार के समय से ही चर्चा में रहा है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक बयान से फिर चर्चा में आ गया है। आधिकारिक रूप से संघ सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। उसका व्यावहारिक राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों का क्या देश की राजनीति से कोई संबंध है या फिर ये दोनों पूरी तरह अलग-अलग क्षेत्र हैं, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। देश के समाजशास्त्र और संस्कृति में से ही राजनीति या राज्य की नीति बनती है। राज्य की नीति मोटे तौर पर किसी भी राज्य का शासक या शासक दल बनाता है। यदि व्यवस्था तानाशाही है तो शासक, लेकिन यदि व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो शासक दल राज्य की नीति का निर्धारक है। यदि राज्य की नीति देश की संस्कृति या समाजशास्त्र से न जुड़ी हो तो वह ज्यादा देर स्थिर नहीं रह सकती। यह दो स्थितियों में संभव है। यदि किसी देश पर विदेशी राज्य का शासन हो जाता है तो जाहिर है कि वह अपने मूल राज्य के हितों के लिए विजित राज्य की नीति का निर्माण करेगा। जैसा भारत के मामले में हुआ था। यहां लम्बे अरसे तक एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल मंगोल) मूल के लोगों का शासन रहा। उसके बाद देश के बड़े हिस्से पर ब्रिटेन राज्य का शासन रहा। थोड़े से हिस्से पर पुर्तगाल व फ्रांस राज्य का शासन रहा। जाहिर है कि इन सभी ने भारत में जिस राजनीति का विकास किया, उसका इस देश की संस्कृति व समाज से कुछ लेना-देना नहीं था। उनकी राजनीति अपने मूल देशों/राज्यों के हितों का संवर्धन करने वाली ही थी। लेकिन यह भी निश्चित ही है कि कोई भी विदेशी शासक किसी दूसरे देश में अपनी राजनीति अपने बलबूते ही कभी भी लागू नहीं कर सकता।

इसके लिए वह विजित देश के ही कुछ लोगों की मदद लेता है। हर युग में ऐसे लोग होते हैं। भारत इसका उदाहरण है। लेकिन स्पष्ट है कि किसी देश की राजनीति और उसकी संस्कृति के परस्पर विरोधी होने का कारण उस देश पर विदेशी राज्य के शासन के कारण ऐसा संभव है। लेकिन यह भी संभव है कि किसी राज्य/देश में शासन वहीं के राजनीतिक दल का हो, लेकिन तब भी उसकी राजनीति वहां के समाजशास्त्र और संस्कृति के विपरीत हो। यह देखने-सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन यह संभव भी है और ऐसा हुआ भी है। इसके लिए रूस का उदाहरण लिया जा सकता है। कई दशक पहले रूस में रूस की ही कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो गया। वह शासन तानाशाही था या लोकतांत्रिक था, यह बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह उस देश का आंतरिक मामला ही माना जाएगा। लेकिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति/राजनीतिक व्यवस्था उस देश की मूल संस्कृति व स्वभाव/प्रकृति के विपरीत थी। इसलिए सात-आठ दशक में ही शासक दल और राजनीति दोनों ही अपदस्थ कर दी गईं। वहां के लोग पुनः अपने परम्परागत प्रतीकों, इतिहास से जुड़ गए। अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य/देश में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न वहां के राजनीतिक प्रश्नों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। ये परस्पराश्रित हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में ही हुई थी। अपने अपने हिसाब से दोनों ने देश के महत्वपूर्ण मसलों/प्रश्नों पर अपने अपने ढंग से विचार करना शुरू किया और उन्हें देश की राजनीति के केन्द्र में स्थापित करने की कोशिश की, ताकि किसी भी राजनीतिक दल का शासन हो, लेकिन वह इन सांस्कृतिक/सामाजिक प्रश्नों से आंख न चुरा सके। लेकिन आज लगभग दस दशकों बाद भारत का कम्युनिस्ट आन्दोलन हाशिए पर चला गया है और संघ द्वारा उठाए गए प्रश्न देश की राजनीति के केन्द्र बिन्दु में आ गए हैं।

ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति रूस की राजनीति की ही तरह, देश की सामाजिक-सांस्कृतिक धारा से नहीं निकली थी। इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी राजनीति में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन उसके मुद्दे देश की राजनीति के केन्द्र में प्रस्तावित हो गए क्योंकि उसके मुद्दे देश की सामाजिक-सांस्कृतिक धारा में से निकले थे। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक राजनीति में न होते हुए भी देश की राजनीति को प्रभावित कर सका और कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति में होते हुए भी न तो देश की राजनीति की दिशा निर्धारित कर सकी और न ही देश की सामाजिक-सांस्कृतिक धारा पर अपना कोई प्रभाव छोड़ सकी। लगभग यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी देश की सामाजिक-सांस्कृतिक धारा से जुड़ी हुई है या नहीं, यह प्रश्न सदा विवादास्पद रहेगा। संघ के संस्थापक डा. हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन करने के निर्णय तक कांग्रेस आन्दोलन के बीच के रास्तों की यात्रा करते हुए ही पहुंचे थे। यह ठीक है कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर की इस आश्चर्यजनक स्थिति पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की क्योंकि वे मानते थे कि यह विदेशी शासन से लडने का समय है, अतः सभी प्रयासों/आंदोलनों को एक दूसरे का पूरक ही मानना चाहिए।

लेकिन डा. भीमराव रामजी अंबेडकर उतने उदार नहीं थे। उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के भीतर का एक्सरे किया और उसकी रपट देश के सामने प्रस्तुत की। अंबेडकर का कहना था कि शुरू में कांग्रेस अपनी राजनीति में देश के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों को जोड़ कर चलती थी। कांग्रेस मानती थी कि देश की राजनीति और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न परस्पर गुंफित हैं। यही कारण था कि जब कांग्रेस का वार्षिक राजनीतिक अधिवेशन होता था तो उसके दूसरे ही दिन उसी पंडाल में कांग्रेस का सामाजिक अधिवेशन होता था। यानी कांग्रेस मान कर चलती थी कि सामाजिक-सांस्कृतिक आधार के बिना देश की राजनीति बंजर व बांझ है। लेकिन बाद में हुए पुणे अधिवेशन में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक रूप से पलटी मारी। उसने सामाजिक-सांस्कृतिक अधिवेशन बन्द ही नहीं किया, बल्कि जो कांग्रेसी वह अधिवेशन करना भी चाहते थे, उनका डटकर विरोध भी किया। इसका अर्थ है कि कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीति को देश के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों से अलग कर लिया। यानी अपनी राजनीति को बांझ बना दिया। कांग्रेस ने ऐसा किन शक्तियों के आग्रह पर किया? क्या इसमें उस समय के ब्रिटिश शासकों का भी कोई हाथ था, यह आज भी शोध का विषय है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक मसलों में युगानुकूल परिवर्तन होता रहता है।

जीवन्त समाज कभी जड़ नहीं हो सकता। वह युग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आपको ढालता रहता है। अंबेडकर मानते थे कि हिन्दु समाज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसमें युगानुकूल परिवर्तन की आन्तरिक व्यवस्था विद्यमान है। यही व्यवस्था उसे सनातन काल से लेकर आज तक प्रगतिशील भी बनाती है और जड़ों से जुड़े रहने की ताकत भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डा. हेडगेवार के समय से लेकर डा. मोहन भागवत तक के काल में देश के इन्हीं सामाजिक-सांस्कृतिक मसलों से बावस्ता रहा है और प्रयास करता रहा है कि देश की राजनीति देश की समाज रचना और संस्कृति के केन्द्र बिन्दु के इर्द-गिर्द निर्मित होनी चाहिए, न कि इनसे किनारा करके। यदि वह ऐसा करती है तो वह बांझ राजनीति होगी। संघ राजनीति में दखलअंदाजी नहीं करता व व्यावहारिक राजनीति में छलांग लगाता है। उसका प्रयास यही रहता है कि देश की राजनीति राज्य और राष्ट्र के स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए, न कि उसके विपरीत।

संपादक की कलम से

ओबीसी प्रमाणपत्र 'अवैध'

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में, 2010 के बाद, सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में सभी सूचियों को भी अवैध और अमान्य करार दिया गया है। दरअसल 5 मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक जिन 42 वर्गों को ओबीसी प्रमाणपत्र दिए गए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी मई, 2011 में सत्ता में आई थीं, लिहाजा उनके कार्यकाल में भी दिए गए ओबीसी प्रमाणपत्र 'असंवैधानिक' करार दे दिए गए हैं। यकीनन यह ममता सरकार के लिए गंभीर धक्का है। अदालत के फैसले से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त हुए हैं। हालांकि जो पहले ही ऐसे आरक्षण का लाभ ले चुके हैं अथवा नौकरियों, सेवाओं में कार्यरत हैं या भर्तियों में चयन हो चुका है, वे अदालत के फैसले से अप्रभावी रहेंगे। मार्च, 2010 से पहले भी ओबीसी के 66 वर्गों में जो वर्गीकृत किए जा चुके हैं, उनसे जुड़े सरकार के कार्यकारी आदेश में भी अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि जनहित याचिकाओं में उनकी पहचान और वर्गीकरण को चुनौती नहीं दी गई है। अलबत्ता उच्च अदालत का जो फैसला सार्वजनिक हुआ है, उसमें मुसलमानों के ओबीसी दर्जे और आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव-प्रचार में यह मुद्दा शिद्दत से उठाते रहे हैं कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दल वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं।

अदालत का यह फैसला उनके गाल पर करारा तमाचा है। गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटना चाहती हैं और उसे मुस्लिम समुदाय को देना चाहती हैं। ममता बनर्जी सरकार ने बिना कोई उचित सर्वे किए 118 मुस्लिम वर्गों को ओबीसी बनाया और फिर आरक्षण भी दिया। उसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के अधिनियम, 1993 के तहत पिछड़ा आयोग की कोई सलाह भी नहीं ली, जबकि राज्य सरकार के लिए ऐसा करना बाध्यता है।'' बहरहाल यह अपनी-अपनी राजनीति है। अदालती फैसले में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बंगाल में मुसलमानों या घुसपैठियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया और फिर आरक्षण सुनिश्चित कर 'वोट बैंक' तैयार कर लिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ के सामने यह मामला आया था, जिसमें ओबीसी के 77 समूहों की पहचान और वर्गीकरण को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा कि उन समुदायों का डाटा नहीं दिया गया, जिनके आधार पर बंगाल सरकार मानती है कि राज्य सरकार की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समुदाय को सिर्फ पिछड़ेपन के आधार पर ही ओबीसी घोषित नहीं किया जा सकता। वे वैज्ञानिक और पहचान योग्य डाटा के आधार पर ही ओबीसी में हैं। समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जनसंख्या तथा अन्य अनारक्षित जमातों को भी शामिल करते हुए आकलन करना जरूरी है। खंडपीठ का यह भी मानना था कि ओबीसी के ऐसे प्रमाणपत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह लिए बिना ही जारी किए गए। तृणमूल कांग्रेस के अभी तक के कार्यकाल में जितने भी ओबीसी प्रमाणपत्र दिए गए हैं, खंडपीठ ने सभी को अमान्य घोषित कर दिया है।

ओबीसी के 37 समुदायों के वर्गीकरण के संदर्भ में खंडपीठ ने 2012 के अधिनियम की धारा 16 को निरस्त कर दिया है। दरअसल यह धारा राज्य सरकार को शक्तियां देती है कि वह किसी भी अनुसूची में संशोधन कर सके। नतीजतन 37 समुदाय भी 2012 के अधिनियम की अनुसूची एक से बाहर कर दिए गए हैं। बहरहाल उच्च न्यायालय का निर्णय राजनीतिक, जातीय, सामाजिक दृष्टि से बेहद गंभीर है।

राय

हिमाचल के भ्रम

चुनावी बिसात पर लड़ रहे मुद्दों के बीच हिमाचल के भ्रम भी डटे हुए हैं। चुनाव न सही कह पा रहा और न ही सुन रहा। वही दो चार अपशब्द, छह बागी पूर्व विधायक, बालीवुड की कंगना और गोदी-मोदी के बीच बंटवारे की हदें खोजता प्रचार। ये चुनाव गुजर जाएंगे, लेकिन लकीरें पीटते हमारे भविष्य के प्रश्न लंबित रह जाएंगे। प्रदेश के समाज, लोगों और सरकारों के ढर्रे को यह भ्रम सदैव रहा है कि हिमाचल यूं ही चलते-चलते एक दिन पुण्य कमा लेगा। यही वजह है कि हर विधायक को अपने-अपने हलके में वह सब कुछ चाहिए, जो सत्ता से बटोर सकता है। अब तो राज्य का यह भ्रम टूट गया कि अपनी औकात पर हम बजट बना ही नहीं सकते, इसलिए अस्सी हजार करोड़ की देनदारी पर भी सत्ता के तिलिस्म में राजनीति चलती है। यहां प्रदेश की आर्थिकी के सिक्के का एक ही पहलू बचा है, चाहे भाजपा आजमा ले या कांग्रेस अपना ले, अंततः हम कर्ज उठाएंगे और कर्मचारियों से लेकर सत्ता के लाभ में हर जगह तथा हर वर्ग में बांट देंगे। हमें यह भ्रम है कि अधिक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय होंगे, तो प्रदेश के मानव संसाधन को चार चांद लगेंगे, लेकिन हमारी शिक्षा की कलई उतर रही है। हम तो बीबीएन में पैदा हो रहे रोजगार के भी काबिल नहीं। अकेले बीबीएन में करीब चार लाख बाहरी राज्यों के लोग रोजगार पा रहे हैं, फिर भी हमें भ्रम है कि सत्तर फीसदी हिमाचली वहां गुलकंद खा रहे हैं।

हिमाचल के हर जिला का सबसे बड़ा कसूरवार रोजगार कार्यालय है, जहां 45 वर्ष की आयु तक सरकारी नौकरी के आवेदन सूखते नहीं और बैच वाइज अगर टीचर भर्ती हो, तो फिर कोई पाठ्यक्रम अहमियत रखता ही नहीं। क्या गजब की सियासी घोषणा है कि जो युवा क्षमता को 45 वर्ष तक सरकारी नौकरी की कतार में खड़ा करके निकम्मा बना रही है। काश! हिमाचल युवा उद्यमशीलता पर गंभीरता से प्रयास करता। हमारी शिक्षा और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के जरिए डिग्रियों की मशीन न साबित होकर युवा वर्ग की जोखिम लेने की क्षमता, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की काबिलीयत, संचार कौशल, नेतृत्व, उत्कृष्टता और नवीन तकनीक की दृष्टि पैदा कर पाते। आश्चर्य यह कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को जम्मू-कश्मीर के विविध पहलुओं पर माथापच्ची से फुर्सत नहीं, जबकि वहां दो केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही हैं। आधी सदी गुजार चुके शिमला विश्वविद्यालय की हालत यह है कि वाणिज्य की पढ़ाई तक को संवार नहीं पाया। हमारे बच्चों में देश के प्रति जुनून व जज्बा है, लेकिन एक भी डिफेंस स्टडीज का स्वतंत्र कालेज नहीं बना पाए। हमारी महत्त्वाकांक्षा जातीय और समुदाय के साम्राज्यों का गठन करना है ताकि हर प्रगति और प्रशंसा में किसी हिमाचली से अधिक हम जाति या वर्ग में पहचाने जाएं। आश्चर्य यह कि हमारे बच्चों को कोई रोल मॉडल या मार्ग दर्शक नहीं मिलता और इसलिए स्कूल-कालेजों के वार्षिक समारोहों में वही नेता हमें भ्रम में जीना सिखा रहे हैं, जो आज तक कुछ नहीं कर पाए।

क्यों न ऐसे समारोहों में नेताओं की उपस्थिति बंद की जाए और कर्म से प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाए। राज्य को भ्रमित करती नीतियां और कार्यक्रम बंदरबांट करते हुए केवल सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में घटिया नस्लें उगा रहे हैं। सत्ता के पद अगर गौर से देखे जाएं, तो वहां सामाजिक प्रतिष्ठा, उत्कंठा व काबिलीयत की सरेआम तौहीन भी सर्वमान्य है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचली समाज अब समुदाय बनकर न तो सोच रहा है और न ही प्रकट हो रहा है। हमें विकास का समुदाय, प्रदेश हित का समुदाय, आर्थिक खुशहाली का समुदाय, आर्थिकी का जवाबदेह समुदाय और भविष्य का समुदाय बन कर सोचना पड़ेगा, वरना चुनाव की रेहड़ी पर हम, आप और प्रदेश यूं ही बिक जाएगा।

भूपिंद्र सिंह

हिमाचली खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर चमक

इस तरह हर जिले में किसी न किसी खेल के लिए प्ले सुविधा उपलब्ध है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छे प्रशिक्षकों व पूर्व खिलाडिय़ों को बुलाकर शिक्षा व खेल विभाग मिलकर खेल अकादमियां खोल दें। प्रदेश के दूरदराज शिक्षा संस्थानों में भी उपलब्ध खेल सुविधा के अनुसार खेल विंग या अकादमी खुलनी चाहिए'

वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को लंबी दूरी की दौड़ में सुमन रावत ने पहला पदक अस्सी के दशक में दिलाया था। उसके बाद स्वर्गीय कमलेश व अमन सैनी हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते रहे थे। तेज गति की दौड़ में पहली बार पुष्पा ठाकुर व भाला प्रक्षेपण में संजो दवी ने पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश के धावकों को स्पीड व थ्रो में भी जीत की राह दिखा दी है। इस वर्ष हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय फैडरेशन कप में कांगड़ा के अंकेश चौधरी ने 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। सेना का यह धावक ऊना खेल छात्रावास में प्रशिक्षक भागीरथ के प्रारंभिक प्रशिक्षण से गुजरा है। सेना से ही जोगिंद्रनगर के सावन बरवाल ने भी इसी प्रतियोगिता की स्पर्धा 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह धावक तत्कालीन राज्य खेल विभाग के प्रशिक्षक गोपाल ठाकुर के प्रशिक्षण से आगे गया है। 1500 मीटर दौड़ में सिरमौर की नितिका, जो बिलासपुर राज्य खेल छात्रावास में प्रशिक्षक राकेश चौधरी की ट्रेनी रही है, ने इसी मीट में प्रदेश के लिए रजत पदक जीता है। अमेरिका में चल रहे एएफ आई के कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही साई खेल छात्रावास धर्मशाला में प्रशिक्षक केहर सिंह पटियाल की तत्कालीन ट्रेनी चंबा की सीमा भी 10000 मीटर दौड़ को ओलंपिक क्वालीफाई के नजदीक दौड़ रही है। अगले महीने ओलंपिक के लिए अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल ट्रायल है। उसमें इन सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी व अन्य कई खेलों में हिमाचली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं। हैंडबाल महिला वर्ग में हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढिया प्रदर्शन कर रहा है। मोरसिंघी हैंडबाल अकादमी पिछले एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश के लिए पदक जीत रही थी, मगर राष्ट्रीय सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक से चूक रही थी। 2021 में बरेली में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबाल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने पिछले तीन सालों की विजेता रेलवे टीम को फाइनल में चार गोलों के अंतर से हराकर विजेता ट्राफी पर पहली बार कब्जा कर अपनी पिछली तीन वर्षों की हार का बदला चुकता कर दिया था। इसके बाद फिर 2022 में भी हिमाचल प्रदेश महिला हैंडबाल टीम ने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश में यह खेल 1982 दिल्ली एशियाड के बाद काफी लोकप्रिय हुआ। बिलासपुर हैंडबाल का शुरू से ही अच्छा केंद्र रहा है। बात चाहे हैंडबाल संघ संचालन की हो या प्रशिक्षण की, बिलासपुर का योगदान सबसे अधिक रहा है। स्नेह व उसके पति सचिन चौधरी के निर्देशन में मोरसिंघी हैंडबाल अकादमी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले 2018 व 2021 के एशियाई खेलों में लगभग एक-तिहाई भारत की टीम इसी अकादमी से प्रशिक्षित थी। कनिष्ठ राष्ट्रीय, स्कूली राष्ट्रीय व अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं में इस अकादमी के बल पर हिमाचल प्रदेश महिला वर्ग में विजेता का ताज पहने है। हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों को थोड़ी बहुत मिली खेल सुविधाओं से यह परफॉर्मेंस सामने आई है। इसलिए सरकारी व निजी क्षेत्र में खेल छात्रावासों व अकादमियों की बहुत जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश में हाई परफॉर्मेंस अकादमियों की भी बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर हिमाचली खिलाडियों का राज्य से पलायन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में पहले से चल रहे खेल छात्रावासों के अतिरिक्त और कई जगह खेल छात्रावास खोलने के लिए बहुत अधिक धन व संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ अधिक होने के कारण यहां एक स्थान पर बड़े मैदान खेल के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए कई खेलों के लिए एक जगह खेल छात्रावास बनाना कठिन कार्य है। इसलिए यहां पर सुविधा व प्रतिभा के अनुसार खेल अकादमी या विंग कामयाब हो सकते हैं। प्रतिभा व सुविधा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी सरकार खेल विंग खोलती है, तो भविष्य में हिमाचल के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई महाविद्यालयों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ढांचा तैयार खड़ा यूं ही बेकार हो रहा है। इस कॉलम के माध्यम से पहले भी इस विषय पर बार-बार लिखा जा चुका है, मगर सरकार का रवैया उदासीन रहा है। खेल विंगों के लिए सरकार को न तो खेल ढांचा खड़ा करना पड़ता है और न ही नया छात्रावास बनाना पड़ता है। केवल खेल विशेष का प्रशिक्षक और खिलाडियों के लिए खुराक व रहने का प्रबंध करना होता है, जो आसानी से बहुत कम धन राशि खर्च करके हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण निजी प्रयत्नों से स्नेह लता ने कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे तो राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, धर्मशाला व बिलासपुर में एथलेटिक्स के विंग आसानी से चल सकते हैं क्योंकि यहां तीनों जगह सिंथेटिक ट्रैक हैं। स्कूलों में भी यहां पर एथलेटिक्स की नर्सरियां स्थापित हो सकती हैं।

ऊना तथा मंडी में तैराकी के लिए तरणताल उपलब्ध हैं। शिलारू व ऊना में एस्ट्रोटर्फ हाकी के लिए बिछी हुई है। इस तरह हर जिले में किसी न किसी खेल के लिए प्ले सुविधा उपलब्ध है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छे प्रशिक्षकों व पूर्व खिलाडियों को बुलाकर शिक्षा व खेल विभाग मिलकर खेल अकादमियां खोल दें। प्रदेश के दूरदराज शिक्षा संस्थानों में भी उपलब्ध खेल सुविधा के अनुसार खेल विंग या अकादमी खुलनी चाहिए। ऊपर जिन खिलाडियों की चर्चा हुई है, उनमें से सभी किसी न किसी सरकारी या शौकिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक खेल अकादमी व विंग खुलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

पूरन सरमा

सबहि भूमि गोपाल की'

अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण की परम्परा हमारे यहां अनादि काल से चली आ रही है। आज जो किले, महल तथा बड़े-बड़े पुरातत्व स्थल हम देखते हैं, वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। राजा की जितनी इच्छा हुई उतनी ही जमीन पर निर्माण कर दिया तथा बेगार रूप में श्रमिकों का शोषण कर लिया। उसी परम्परा का निर्वहन हमारे देश में इन दिनों बखूबी किया जा रहा है। 'सबहि भूमि गोपाल की' की तर्ज पर भारतीय नागरिक भूमि हड़पो अभियान के कुशल खिलाड़ी बनकर निर्माण एवं अतिक्रमण की दिशा में सक्रिय हैं। 'राम नाम की लूट है' वाला मुहावरा भी इस समय पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है या यह भी कह सकते हैं कि 'सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का।' सभी के बालम पुलिस में भर्ती होंगे तो कानून दम नहीं तोड़ेगा तो क्या अपना डंडा चलाएगा? कानून का डंडा छोटा होता जा रहा है तथा अराजकता का एक सुखद मनभावन वातावरण नए रूप में तैयार हो रहा है, जिससे गोपाल की इस भूमि को महापुरुष हड़प कर रहे हैं। इस मामले में हर नागरिक 'वसुधैव कुटुंबकम' विचारधारा का समर्थक हो गया है। भूमि हड़पने का अभियान आम चुनाव के समय बेतहाशा पाया जाता है। पहले लोकसभा चुनाव की आड़ में लोग रातों-रात महल चिनाते रहे तो अब प्रजातंत्र में विधानसभा चुनाव का शोर होने से सारे नियम तोड़ कर लोग जमीनों को पाटने में लगे हैं। रात को सोए थे, तब खाली जगह थी, सुबह उठे तो दीवारें सिर उठाए खड़ी हैं।

कोई दुकान बना रहा है तो कोई मंजिल चढ़ा रहा है। कोई मकान से दुकान निकाल रहा है तो कोई आवास समस्या के स्थायी हल के लिए नगर प्रशासन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार मूक बनी सब देखती रहती है क्योंकि उसे अभी जनता का वोट लेना है और वोट के सामने सात खून भी माफ करने का हमारे यहां रिवाज चल रहा है। कोई छज्जा निकाल रहा है तो कोई खिडक़ी खोद रहा है। कोई मंदिर बना रहा है तो कोई मस्जिद। कोई यों ही पत्थर लाल पोतकर धार्मिक भावना के आधार पर भूमि हड़पो की दिशा में पहल करने की चाल चल रहा है। रातों-रात हजारों की संख्या में मकान बन गए हैं। यह नगर भले अपनी रंगत व खासियत खोदे, लेकिन जमीन हड़पो के संचालक पूरे मनोयोग से कंकरीट का जंगल उगाने में लगे हैं। आदमी की महत्त्वाकांक्षाएं इन दिनों पूरे जोर पर हैं। जिसके एक मकान है, वह दूसरा बना रहा है, जिसके दूसरा है, वह तीसरा बना रहा है। मकान क्या, मकबरे बना रहा है। असीम इच्छाएं सिर उठाकर अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण को प्रेरित करती हैं और नागरिक चुनाव की आड़ में अपनी कारगुजारियां कर रहे हैं। देखा-देखी ज्यादा हो रही है। पड़ोस में किसी ने एक फुट का अतिक्रमण किया, तो दूसरे ने चार फुट को घेर लिया। अवैध निर्माण जिसने पचास वर्ग गज में किया, उससे जुडने की यह परम्परा दिनों-दिन विकसित हो रही है। जब तक आदमी को अपनी माटी से प्रेम नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय भावना का अभ्युदय असंभव है। इस मामले में सारे भूमि हड़पो कार्यकर्ता एक हैं।

इनसाइड

विदेशी मुद्रा भंडार 648.7 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर, बाहरी निवेशकों का बढ़ रहा भरोसा

यह लगातार तीसरा सप्ताह जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। 17 मई से पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.561 अरब डॉलर बढ़कर 644.151 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा गया था।

मुंबई। 17 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.549 अरब डालर बढ़कर 648.7 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा सप्ताह जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। 17 मई से पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.561 अरब डॉलर बढ़कर 644.151 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था।

लगातार कई सप्ताह की वृद्धि के बाद पांच अप्रैल को विदेशी मुद्रा भंडार 648.562 अरब डॉलर के अब तक के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। आरबीआई ने कहा कि 17 मई को समाप्त सप्ताह में सोने का भंडार 1.244 अरब डॉलर बढ़कर 57.195 अरब डॉलर हो गया।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 11.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.168 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक के आंकड़ों से पता चलता है समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 16.8 करोड़ डॉलर घटकर 4.327 अरब डॉलर हो गई।

इस सरकारी स्कीम में निवेशक को मिलता है तगड़ा रिटर्न, मैच्योरिटी पर 1 करोड़ पाने के लिए रोज करना होता है बस इतना इन्वेस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

वर्तमान में निवेश के लिए कई सरकारी स्कीम मौजूद है। अगर आप एक ऐसी स्कीम की तलाश कर रहे हैं जहां हाई रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट मिले तो आप पीपीएफ (Public Provident Fund) में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको मैच्योरिटी पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल सकती है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

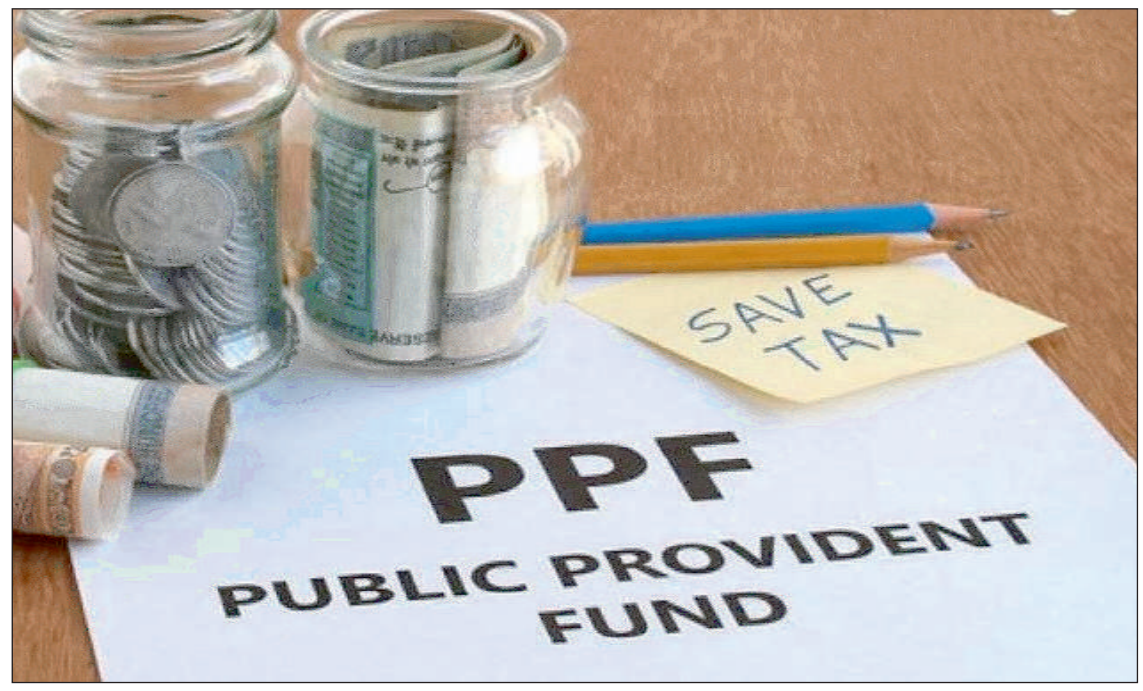

नई दिल्ली। करोड़पति बनने का हर किसी का सपना होता है। इसके लिए कई लोग जॉब के साथ ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है।

अगर आप भी कोई सिक्योर सेविंग स्कीम (Saving Scheme) की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपको सरकार द्वारा (Government Scheme) चलाई जा रही पीपीएफ स्कीम (Public Provident Fund) के बारे में बताएंगे।

इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं है और इस पर उच्च ब्याज भी मिलता है। अगर आप इस स्कीम में रोजाना 405 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 1 करोड़ रुपये भी मिल सकते हैं।

पीपीएफ पर मिलता है शानदार ब्याज (PPF Interest Rate)

बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तुलना में पीपीएफ स्कीम में ज्यादा ब्याज मिलता है। वर्तमान में सरकार इस स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है। सरकार द्वारा इस स्कीम पर चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) दिया जाता है। हर कारोबारी साल के आखिरी महीने यानी मार्च में निवेशक के पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में ब्याज का भुगतान होता है।

कितना करना होता है निवेश

पीपीएफ के वेबसाइट के अनुसार इस स्कीम में सालाना न्यूनतम 500 रुपये का निवेश और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर कोई निवेशक पूरे वित्त वर्ष में निवेश नहीं करता है तो पीपीएफ अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए निवेशक को निवेश राशि के साथ पेनल्टी का भी भुगतान करना होता है।

टैक्स बेनिफिट का मिलता है फायदा (PPF Tax Benefit)

इस योजना की खास बात है कि यह पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free Scheme) है। इसमें निवेश राशि, ब्याज और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है।

कितने साल में मैच्योर होती है स्कीम

इस स्कीम में निवेशक को 15 साल तक निवेश करना होता है। इसका मतलब है कि स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड (PPF Maturity Period) 15 साल का होता है। निवेश चाहे तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी निवेश को जारी रख सकता है। हां, निवेशक पीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। इसके लिए उसे मैच्योरिटी से एक साल पहले आवेदन देना होगा।

मैच्योरिटी से पहले कर सकते हैं निकासी

पीपीएफ स्कीम में निवेशक मैच्योरिटी से पहले भी आंशिक निकासी कर सकते हैं। निवेशक आपात स्थिति में पीएफ अकाउंट में जमा राशि में से 50 फीसदी निकाल सकता है। हालांकि, जब पीएफ अकाउंट को 6 साल हो जाए उसके बाद ही आंशिक निकासी की जा सकती है।

यहां तक कि पीएफ अकाउंट में 3 साल तक निवेश के बाद लोन भी लिया जा सकता है। निवेशक को पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 25 फीसदी ही लोन मिलता है। लोन की रिपेमेंट टेन्योर 36 महीने का होता है और इस पर 2 फीसदी का ब्याज लगता है।

पीपीएफ स्कीम से कैसे बन सकते हैं करोड़पति?

पीपीएफ स्कीम एक तरह से करोड़पति स्कीम (Crorepati Scheme) है। अगर निवेशक हर दिन 405 रुपये का निवेश करता है तो वह सालाना 1,47,850 रुपये का निवेश करेगा। अगर वह 25 साल तक अकाउंट में निवेश करता है और उसे 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है तो उसे मैच्योरिटी के वक्त 1 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि मिलेगी।

अडानी ग्रुप के लिए दो गुड न्यूज! हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला घाटा खत्म, सेंसेक्स में शामिल होगी

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी पो र्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स में शामिल होगी। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी की अदाणी पोर्ट 30 शेयरों वाले सूचकांक में आईटी कंपनी विप्रो का स्थान लेगी। यह बदलाव 24 जून से प्रभावी होगा। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी की अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर फरवरी 2023 वाली गिरावट से उबरकर करीब तीन गुना बढ़ गया है।

नई दिल्ली। अदाणी समूह की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स में शामिल होगी। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी की अदाणी पोर्ट 30 शेयरों वाले सूचकांक में आईटी कंपनी विप्रो का स्थान लेगी। यह बदलाव 24 जून से प्रभावी होगा।

सेंसेक्स में शामिल होने वाली यह अदाणी समूह की पहली कंपनी होगी। समूह की कुल 10 कंपनियां बाजार में सूचीबद्ध हैं और इस समय इनका संयुक्त पूंजीकरण 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड सेंसेक्स 50 में शामिल होगी। वहीं, डिवी लैबोरेट्रीज लिमिटेड सेंसेक्स 50 से बाहर होगी।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला घाटा मिटा

अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर जनवरी 2023 में आई अमेरिकी शार्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पहले के स्तर को पार कर गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने से पहले 24 जनवरी 2023 को कंपनी के शेयर 3,442 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए थे।

शुक्रवार को बीएसई में यह दिनभर के कारोबार में 3,456.25 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंचे। हालांकि, कारोबार के अंत में यह 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,384.65 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की सभी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में करीब 150 अरब डॉलर की गिरावट हुई थी।

मशहूर इकोनॉमिस्ट ने की विरासत टैक्स की वकालत, कहा- इसी से भारत में दूर होगा अमीरों और गरीबों के बीच फासला

भारत में पिछले दिनों ने विरासत टैक्स का मुद्दा काफी जोरशोर से उठा। इस पर काफी सियासत भी हुई। अब मशहूर फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी (Thomas Piketty) ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में सुझाव दिया है कि भारत को 10 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर 2 फीसदी सालाना टैक्स और 33 फीसदी विरासत टैक्स लगाना चाहिए।

नई दिल्ली। भारत में पिछले दिनों ने विरासत टैक्स का मुद्दा काफी जोरशोर से उठा। इस पर काफी सियासत भी हुई। अब मशहूर फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी (Thomas Piketty) ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में सुझाव दिया है कि भारत को 10 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर 2 फीसदी सालाना टैक्स और 33 फीसदी विरासत टैक्स (inheritance tax) लगाना चाहिए। इससे देश को बढ़ती आर्थिक असमानता दूर करने में मदद मिलेगी।

क्या है पिकेटी के रिसर्च पेपर में

पिकेटी ने अपने रिसर्च पेपर 'प्रपोजल्स फऑर ए वेल्थ टैक्स पैकेज टु टैकल एक्स्ट्रीम इनइक्वलिटीज इन इंडिया' अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि नए टैक्स प्रावधान से आर्थिक असमानता तो दूर होगी ही, सरकार को सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए धन भी मिलेगा।

पिकेटी अपने रिसर्च पेपर में कहते हैं, 'अगर सरकार 10 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले पर 2 फीसदी सालाना टैक्स और 33 फीसदी विरासत टैक्स लगाती है, तो इसका 99.96 फीसदी वयस्क आबादी पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही, इससे सरकार की तिजोरी भी भर जाएगी। उसके राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.73 फीसदी बढ़ जाएगा। इससे सरकार को मौका मिलेगा कि वह गरीब और मध्यम वर्ग के बेहतर नीतियां तैयार कर सके।'

शिक्षा पर खर्च हो सकेगा दोगुना

पिकेटी नई नीतियों का उदाहरण भी देते हैं। उनका कहना है कि नए टैक्स से सरकार बड़े आराम से शिक्षा पर अपने खर्च को करीब दोगुना कर सकेगी। यह पिछले 15 साल से जीडीपी के करीब 3 फीसदी पर स्थिर है। यह 6 फीसदी लक्ष्य से काफी कम है, जिसे सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में में तय किया था।

इस रिसर्च पेपर को थॉमस पिकेटी (पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब), लुकास चांसल (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल एंड वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब) और नितिन कुमार भारती (न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब) ने लिखा है।

इनके पेपर के मुताबिक, भारत में आर्थिक असमानता फिलहाल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसका सामाजिक अन्याय के साथ गहरा संबंध है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि भारत में शीर्ष 1 फीसदी अमीरों के पास हद से ज्यादा पैसे और संपत्ति है। भारत यहां आर्थिक असमानता के मामले में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देता है।

फिर गिरे सोने के दाम, तीन दिनों में 2000 रुपये से ज्यादा कम हो चुकी है कीमत; चांदी में भी गिरावट जारी

सोने की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट देखी गई और यह 900 रुपये की गिरावट के साथ 72650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। बता दें कि बुधवार को 50 रुपये की मामूली गिरावट के एक दिन बाद गुरुवार को पिछले सत्र में गोल्ड 1050 रुपये गिरकर 73550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 500 रुपये टूटकर 92100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में नरम रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट देखी गई और यह 900 रुपये की गिरावट के साथ 72,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।

बुधवार को 50 रुपये की मामूली गिरावट के एक दिन बाद गुरुवार को पिछले सत्र में कीमती धातु 1,050 रुपये गिरकर 73,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार लगातार तीसरे दिन अपनी गिरावट को बढ़ाते हुए, उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़ों के बाद पीली धातु में गिरावट आई, जिसने इस शर्त को मजबूत किया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबी अवधि के लिए ब्याज दरों को ऊंचा रखेगा।

500 रुपये गिरी चांदी की कीमत

इस बीच, चांदी भी 500 रुपये टूटकर 92,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में यह 92,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, रविदेशी बाजारों से मंदी का संकेत लेते हुए दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 900 रुपये की गिरावट के साथ 72,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं।

वैश्विक बाजारों में सोने की कीमत

वैश्विक बाजारों में, कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,340 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 35 अमेरिकी डॉलर कम है।

एसएंडपी ग्लोबल फ्लैश मई कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सभी अनुमानों को पार करते हुए अप्रैल 2022 के बाद

से अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया।

गांधी ने कहा कि डेटा जारी होने के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार और डॉलर सूचकांक में बढ़ोतरी हुई, जिससे पीली धातु की कीमतों पर असर पड़ा। चांदी भी गिरावट के साथ 30.45 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बोली जा रही थी।

इस सप्ताह सोना कमजोर रहा है, साप्ताहिक ऊंचाई से 2,800 रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण बिकवाली का अनुभव हुआ है। यह गिरावट मुख्य रूप से यूएस फेड द्वारा दरों में जल्द कटौती की संभावना कम होने के कारण है, जैसा कि हाल की बैठक के मिनटों से संकेत मिलता है।

एक साल में 368 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न, पर नतीजों ने किया निराश; शेयरों में लगा लोअर सर्किट

रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर- सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयर पिछले एक साल से काफी चर्चा में रहे। इसने 368 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। लेकिन जब कंपनी ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी किया तो निवेशक काफी निराश हुए। चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च के दौरान सुजलॉन का मुनाफा 278 करोड़ रुपये से घटकर 254 करोड़ रुपये पर आ गया। इसमें करीब 21 फीसदी की गिरावट आई है।

नई दिल्ली। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर- सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयर पिछले एक साल से काफी चर्चा में रहे। इसने 368 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। लेकिन, जब कंपनी ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी किया, तो निवेशक काफी निराश हुए।

चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च के दौरान सुजलॉन का मुनाफा 278 करोड़ रुपये से घटकर 254 करोड़ रुपये पर आ गया। इसमें करीब 21 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 1,690 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,179 करोड़ रुपये हो गया।

कैसी है सुजलॉन की ऑर्डर बुक?

सुजलॉन एनर्जी के पास फिलहाल कुल ऑर्डर 3.3 गीगावाट हैं। इसमें 31 मार्च, 2024 तक 2,929 मेगावाट की ऑर्डर बुक, इसके बाद 402 मेगावाट के सुरक्षित ऑर्डर शामिल हैं। सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा, रहम पिछले वित्त वर्ष के दौरान टेक, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट समेत सभी क्षेत्रों में ठोस आधार बनाने में सक्षम रहे।'

नतीजों के बाद लोअर सर्किट

वित्त वर्ष 2024-25 का पहला ऑर्डर मिलने के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पिछले दो दिनों से अपर सर्किट लग रहा था। लेकिन, नतीजों के बाद निवेशकों को काफी निराशा हुई और उन्होंने जमकर बिकवाली की। आखिर में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगने के बाद ट्रेडिंग रोक दी गई। यह शेयर 45.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

सुजलॉन के शेयरों का हाल

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने पिछले एक साल में 368 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में निवेशकों को 800 फीसदी से अधिक का लाभ हुआ है। हालांकि, पिछले 6 महीने से इसमें सुस्ती बनी हुई है और इसने निवेशकों को सिर्फ 18 फीसदी का मुनाफा दिया है। कमजोर नतीजों के बाद यह कुछ और वक्त तक सुस्ती बनी रहने की आशंका है।

पिछले साल से ज्यादा हुई गेहूं की खरीद, जानिए कितना है सरकार पास भंडा

इस साल सरकार ने गेहूं की बंपर खरीद की है। मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद पिछले साल के कुल 2.62 करोड़ टन से अधिक हो गई है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी उत्तरी राज्यों की है। सरकार का कहना है कि गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक फिलहाल में केंद्रीय पूल में 600 लाख टन से अधिक है जो मौजूदा सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नई दिल्ली। इस साल सरकार ने गेहूं की बंपर खरीद की है। मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद पिछले साल के कुल 2.62 करोड़ टन से अधिक हो गई है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी उत्तरी राज्यों, खासकर पंजाब और हरियाणा की है, जहां से बड़े पैमाने पर गेहूं की सप्लाई हुई है।

22.31 करोड़ किसानों को MSP का लाभ

सरकार ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय पूल के लिए 262.48 लाख टन रबी (सर्दियों) का अनाज पहले ही खरीदा जा चुका है। इससे 59,715 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। अगर खरीदारी करने वाले राज्यों की बात करें, तो सबसे अव्वल पंजाब रहा। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर रहा।

इस बार आवक के हिसाब से खरीद

गेहूं की खरीद आम तौर पर अप्रैल से मार्च तक चलती है। लेकिन केंद्र ने इस साल राज्यों को फसल की आवक के आधार पर खरीद करने की अनुमति दी है। अधिकांश राज्यों में गेहूं की खरीद मार्च की शुरुआत में शुरू हुई। सरकार ने मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 30-32 करोड़ टन तय किया है। धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है।

खाद्यान्न जरूरतों के लिए पर्याप्त भंडार

सरकार का कहना है कि गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक फिलहाल में केंद्रीय पूल में 600 लाख टन से अधिक है। इससे देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ बाजार के लिए अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में है।

गेहूं निर्यात पर है प्रतिबंध

भारत गेहूं का बड़ा निर्यातक है। कोरोना और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इसने कई देशों की जरूरतों को पूरा किया। लेकिन, अप्रैल 2022 में मौसम की गड़बड़ी के चलते फसल खराब हुई। उसके बाद सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो अभी तक जारी है।

विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल रेवन्ना को थमाया कारण बताओ नोटिस, राजनयिक पासपोर्ट रद्द को लेकर एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात

परिवहन विशेष न्यूज

विदेश मंत्रालय ने जदएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद कर दिया जाना चाहिए? अधिकारियों ने गुरुवार को कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि वह फिलहाल जर्मनी में हैं।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने जदएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद कर दिया जाना चाहिए? प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद करने का अनुरोध किया है।

कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि वह फिलहाल जर्मनी में हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रज्वल का पासपोर्ट रद करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के तहत उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उनको ईमेल के जरिये भेजा गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विदेश मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद करने का अनुरोध 21 मई को प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रद करने के लिए हमें न्यायिक अदालत या पुलिस के अनुरोध की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से यह अनुरोध 21 मई को मिला था। हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की।

विदेश मंत्री ने क्या कहा?

भाजपा पर प्रज्वल को बचाने के कांग्रेस सरकार के आरोपों पर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया। मेरा मतलब है, यह पहला मामला नहीं है जब पासपोर्ट रद किया जा रहा है।

आइएएनएस के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शुक्रवार को कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का परिवार उनके बारे में सब कुछ जानता है। जब प्रज्वल रेवन्ना को उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में पूछा गया कि उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा, तो सिद्दरमैया ने सवाल किया-क्या प्रज्वल अपने परिवार को सूचित किए बिना चले गए हैं? क्या वह अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में नहीं हैं?

सिद्दरमैया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ अनाप-शनाप बातें करके अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

दादा की चेतावनी पर ध्यान दें प्रज्वल- जी परमेश्वर

इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को अपने दादा की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए और कानून का सामना करने के लिए तुरंत लौट आना चाहिए। बताते चलें, देवेगौड़ा ने एक खुला पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना को आत्मसमर्पण करने या परिवार के गुस्से का सामना करने को कहा था।

प्रचंड गर्मी के बीच IMD ने दी खुशखबरी, UP समेत इन राज्यों के लिए चक्रवाती तूफान होगा मेहरबान; तापमान में आएगी गिरावट

बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवातीय तूफान का असर व्यापक होने जा रहा है। पांचवें दिन (28 मई) से यह तूफान उत्तर-पश्चिम भारत की हवा का रुख भी बदल देगा जिससे अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आएगी।आईएमडी के अनुसार जम्मू-कश्मीर पंजाब एवं हरियाणा में अभी लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले चार दिनों तक गर्म हवा चलती रह सकती है।

नई दिल्ली। राजस्थान एवं दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत के पांच राज्यों को अभी तीन-चार दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। किंतु बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवातीय तूफान का असर व्यापक होने जा रहा है। पांचवें दिन (28 मई) से यह तूफान उत्तर-पश्चिम भारत की हवा का रुख भी बदल देगा, जिससे अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आएगी।

उत्तर भारत में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत?

पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, लेकिन हवा में नमी की मात्रा ज्यादा रहने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान है कि चार दिनों के बाद चक्रवाती तूफान के असर से उत्तर भारत की हवा का रुख बदलकर पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। इसमें नमी नहीं रहेगी, जिससे उमस वाली गर्मी से राहत मिल सकेगी।

चक्रवाती तूफान बरपा सकता है कहर

स्काइमेट के प्रवक्ता महेश पलावत के अनुसार, चक्रवाती तूफान की गति 80 से 100 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, जो अगले तीन दिनों में एक बड़े सर्किल में उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा की दिशा को बदल देगा। तब तक गर्मी के तेवर में कोई कमी की उम्मीद नहीं है।

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

इस बीच, भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पश्चिम भारत में अगले चार दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में तापमान शुक्रवार को भी अपने उच्चतम शिखर पर है। फलौदी में 49.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में 48.3 एवं जोधपुर में 47.6 डिग्री तापमान रहा। बाड़मेर में शुक्रवार को भी 48.2 डिग्री तापमान रहा। एक दिन पहले यहां 48.8 डिग्री पहुंच गया था। हालांकि, दिल्ली के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। किंतु गर्मी से राहत नहीं है।

इन राज्यों में चलेगी लू

आईएमडी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, पंजाब एवं हरियाणा में अभी लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले चार दिनों तक गर्म हवा चलती रह सकती है। आईएमडी ने राजस्थान एवं गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 28 मई तक पंजाब के लिए भी रेड अलर्ट है।

यहां तक कि हिमालय क्षेत्र हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए भी अगले चार दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत में प्री-मानसून बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगले चार दिनों तक केरल एवं अंडमान निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

में पूरी तरह स्वस्थ हैं और महीनों से प्रचार कर रहे हैं : नबीन पटनायक

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : तीसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी पर निशाना साधा है । चुनावी सभा में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है । बीजेपी झूठ बोलने की हद पार कर चुकी है । मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं और कई महीनों से पूरे राज्य में प्रचार कर रहा हूं।ये कहकर नवीन ने बीजेपी को कड़ा जवाब दिया । इससे पहले बीजेपी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही नवीन के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे । नवीन भी कई बैठकों में कहते थे कि उन्हें आराम करना चाहिए । जिस पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कड़ा जवाब दिया है । वहीं बिजेड़ी नेता भि के पांडियन ने कहा, बीजेपी नेता नए विचार लाने के बजाय आधारहीन बातें कर रहे हैं । ओडिशा के लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम पर इस तरह की बदनामी को स्वीकार नहीं करेंगे। में पूरी तरह स्वस्थ हैं और महीनों से प्रचार कर रहे हैं । बीजेपी ने झूठ बोलने की हद पार कर दी है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनाव के दौरान बीजेपी को कड़ा जवाब दिया ।

शाहपुरा जिले के राजकीय छात्रावात्सो में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शाहपुरा जिले में संचालित राजकीय छात्रावात्सो में सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम अवतार जाट ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रायें 30 जुलाई 2024 तक ई-मित्र के माध्यम अथवा स्वयं की SSO ID से ऑनलाईन आवेदन नवीन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से कर सकते है, जिसकी मेरिट आधार पर प्रवेश सूचियां जारी होगी। राजकीय छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं शिक्षण के साथ कठिन विषय (अग्रेजी, गणित एवं विज्ञान) की कॉचिग की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

'सूचना तकनीकी के दौर में बदला लड़ाई का परिदृश्य बदला', NDA पासिंग आउट परेड में सेना प्रमुख ने और क्या कुछ कहा?

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने युद्ध की प्रकृति के तेजी से बदलने की व्याख्या करते हुए कहा कि अंतरिक्ष साइबर और सूचना तकनीकी के दौर में लड़ाई का परिदृश्य ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 61वें कोर्स में यह नए रंगरूट अगले साल तक कमिश्नड अफसर बन गए होंगे और युद्ध क्षेत्र की कमान संभालने को मिलेगा। एक सच्चे नेतृत्व को उदाहरण पेश करना चाहिए।

पुणे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने युद्ध की प्रकृति के तेजी से बदलने की व्याख्या करते हुए कहा कि अंतरिक्ष, साइबर और सूचना तकनीकी के दौर में लड़ाई का परिदृश्य ही बदल गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 146वें कोर्स के पूर्ण होने पर पासिंग आउट परेड के अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सेना के कैडेटों से प्रभावशाली अभियानों के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि एनडीए के 61वें कोर्स में यह नए रंगरूट अगले साल तक कमिश्नड अफसर बन गए होंगे और युद्ध क्षेत्र की कमान संभालने को मिलेगा। एक सच्चे नेतृत्व को उदाहरण पेश करना चाहिए। साथ ही उनके मातहत काम करने वालों के भरोसे को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। आप सभी की पृष्ठभूमि अलग है पर आप सब में जो एक चीज समान है, आपने देश का सैनिक बनना चुना है।

अपनी उपलब्धियों पर होना चाहिए आपको गौरवान्वित- सेना प्रमुख

सेना प्रमुख ने आगे कहा कि आपकी उम्र के बहुत से युवा इसमें सफल होने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें चयनित होते हैं। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वितहोना चाहिए। आपको याद रखना होगा कि आपके इस सफर में बहुत आगे तक जाना है। आपको आपका कौशल और लोहा साबित करने के बहुत से अवसर मिलेंगे। इसलिए अंतहीन मित्रताएं कीजिए।

मार्गदर्शन के लिए बनाएं अपने मेंटर

उन्होंने कहा कि आपके यह संपर्क भी समय-समय पर आपकी परीक्षा में आपके साथी होंगे। अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए अपने रोल मॉडल और मेंटर बनाइये। सेना प्रमुख ने कहा कि परेड में शामिल हुई महिला कैडेट सच्चे अर्थों में नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। नए कमीशनड दल में 24 महिला कैडेट हैं। परेड में कुल 1265 कैडेट शामिल हुए जिनमें से 337 कैडेट इस साल पासिंग आउट कोर्स को पूरा कर रहे हैं।

कौन थे ऋषि कश्यप जिन्हे परशुराम ने धरती का किया दान और कहलाए सृष्टि के निर्माता

भगवान परशुराम के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और साथ ही कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। इनकी गणना सप्तर्षि गणों में की जाती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार वह ऋग्वेद के सात प्राचीन ऋषियों, सप्तर्षियों में से एक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने समुद्र और धरती पर हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनमें से एक मरीची थे। कश्यप ऋषि मरीची जी के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की बेटी व भगवान कपिल देव की बहन थीं। अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप व तप के बल पर उनकी गिनती श्रेष्ठतम महान विभूतियों में होती थी। मान्यता है कि सृष्टि की रचना में कई ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया। जब हम सृष्टि के विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ जीव, जन्तु या मानव की उत्पत्ति से होता है। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए. कश्यप जी की 17 पत्नियां थीं, जिनके वंश से सृष्टि का विकास हुआ। कश्यप ऋषि को सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यता है कि कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है. पुराण के अनुसार, कश्यप जी की पत्नियों से ही मानस पुत्रों का जन्म हुआ। जिसके बाद से इस सृष्टि का सृजन हुआ। इसीलिए महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक या सृष्टि के सृजनकर्ता कहलाए। कश्यप एक प्रचलित गोत्र का भी नाम है। यह एक बहुत व्यापक गोत्र है। कहते हैं कि जिस मनुष्य का गोत्र नहीं मिलता उसका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है, क्योंकि एक परम्परा के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से हुई। भगवान परशुराम को ऋषि कश्यप के शिष्य थे। कथा के अनुसार, एक बार परशुराम जी ने पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर जब समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया. जिसके बाद उन्होंने पूरी धरती को अपने गुरु कश्यप मुनि को दान कर दी, जिसके बाद कश्यप जी ने परशुराम से कहा-अब तुम मेरे देश में मत रहो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने प्रत्येक रात पृथ्वी पर न रहने का संकल्प किया। वह रोजाना रात्रि में मन के समान तेज गमन शक्ति से महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023